डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2024-2026
लाइसेंस क्र. Tech/23-04/08/2024-2026
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 17.03.2025 से 23.03.2025 ▶ वर्ष-42 ▶ अंक-12 ▶ मूल्य ₹ 10.00

विकसित मध्यप्रदेश @2047 के लिए नागरिकों से प्राप्त किए जाएंगे सुझाव

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में राज्य नीति आयोग द्वारा बनाए जा रहे विकसित मध्यप्रदेश विजन डॉक्यूमेंट के लिए नागरिक सर्वे का शुभारंभ किया। विकसित मध्यप्रदेश@2047 के निर्माण में आमजन की भागीदारी और उनका अभिमत जानने के उद्देश्य से नागरिक सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। इस सर्वे के लिए वेबसाइट के साथ ही एक क्यूआर कोड भी उपलब्ध करवाया गया है, जहां आम व्यक्ति भी नागरिक सर्वेक्षण में हिस्सा लेकर विभिन्न सुझाव दे सकेंगे। विकसित मध्यप्रदेश @2047 के निर्माण में प्रदेश के सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। हमारा यह प्रयास है कि यह विज़न डॉक्यूमेंट केवल सरकार का दस्तावेज न होकर जनता का दस्तावेज बने। इसी उद्देश्य से इसके निर्माण की प्रक्रिया में विषय-विशेषज्ञों, हितधारकों और विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ व्यापक रूप से प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं और सुझावों को सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश का भविष्य हमारे बच्चे हैं और उनकी आकांक्षाओं को इस विज़न में स्थान देने के लिए प्रदेश के विद्यालयों में विकसित मध्यप्रदेश @2047 विषय पर निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस प्रक्रिया में 2.5 लाख से अधिक नागरिकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसी कड़ी में नागरिक सर्वेक्षण का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक नागरिकों का अभिमत प्राप्त किया जा सके। यह सर्वेक्षण हमें बताएगा कि मध्यप्रदेश की जनता वर्ष 2047 का मध्यप्रदेश कैसा देखना चाहती है और किन महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विधानसभा परिसर में वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना हमारा मुख्य लक्ष्य - मुख्यमंत्री

विधानसभा में बजट 2025-26 प्रस्तुत होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की

- मध्यप्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट।
- वर्ष 2003-04 की तुलना में 21 गुना बड़ा है वर्ष 2025-26 का बजट।
- बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया है और न ही कोई कटौती की गई है।
- वर्ष-2029 तक बजट के आकार एवं प्रदेश की जीएसडीपी को दोगुना करने का है लक्ष्य।
- जेण्डर बजट, बाल बजट और कृषि संबंद्ध क्षेत्र में, विगत 6 वर्षों में हुई दोगुना से अधिक की वृद्धि।

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में प्रस्तुत प्रदेश के वर्ष 2025-26 के बजट के संबंध में मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव, गरीब सहित सभी के लिए व्यवस्थित योजना से मध्यप्रदेश विकास और जनकल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत@2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। राज्य का बजट 2025-26 इसी संकल्प की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने पहली बार 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट प्रावधान विगत वर्ष 2024-25 की अपेक्षाकृत 15 प्रतिशत अधिक है।

5 साल में बजट को दोगुना करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में बजट को दोगुना करने का लक्ष्य तय कर लिया गया है। वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य के गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी (ज्ञान) सहित सभी वर्गों की बेहतरी के संकल्प को पूरा किया गया है। सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जा रही है। वर्ष 1956 में मध्यप्रदेश का गठन हुआ, लेकिन वर्ष 2003-04 तक मात्र 20 हजार करोड़ रुपये का बजट था, अब हम इसे 21 गुना बढ़ाते हुए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये तक पहुंचे हैं।

राज्य की उपलब्धियां

- नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक प्रतिवेदन में राज्य को व्यय की गुणवत्ता में प्रथम स्थान मिला है।
- अधोसंरचना क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में विगत वर्ष 2024-25 की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

राज्य की क्षेत्रवार उपलब्धियां

- राज्य शासन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध है, 6 वर्षों में जेण्डर बजट का आकार दोगुना हुआ है।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र में, विगत 6 वर्षों में दोगुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- विगत 6 वर्षों में बाल-बजट का प्रावधान दोगुना से अधिक हुआ।

नारी सशक्तिकरण

- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,183 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

/संक्षिप्त खबर/

आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश की तीव्र प्रगति का प्रमाण- मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25, विकास पथ पर तीव्र गति से बढ़ रहे मध्यप्रदेश के कदमों का प्रमाण है। विभिन्न सूचकांक प्रदेश की प्रगति में सरकार के प्रयासों के साथ नागरिकों के सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण का भी योगदान शामिल है। मध्यप्रदेश, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। जहां एक ओर वर्ष 2023-24 में प्रचलित भावों पर मध्यप्रदेश का घरेलू उत्पाद 13 लाख 53 हजार 809 करोड़ रुपये था, वहीं इसमें 11.05 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 15 लाख 03 हजार 395 करोड़ रुपये पहुँच गया है। यह प्रगति प्रदेश की सशक्त अर्थव्यवस्था और विकास को दर्शाती है।

भीतर के पृष्ठों पर

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **खेल चर्चा** - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

प्रदेश की 18 यूनेस्को विश्व धरोहर में 15 टेंटेटिव और 3 स्थाई सूची में शामिल

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि यूनेस्को ने प्रदेश की चार ऐतिहासिक धरोहरों को सीरियल नॉमिनेशन के तहत टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। सम्राट अशोक के शिलालेख, चौसठ योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के महल और किलों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में घोषित होना प्रमाणित करता है कि मध्यप्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के कारण देश में विशेष स्थान रखता है। गत वर्ष भी यूनेस्को ने प्रदेश की 6 धरोहरों, ग्वालियर किला, बुरहानपुर का खूनी भंडारा,

चंबल घाटी के शैल कला स्थल, भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर, मंडला स्थित रामनगर के गोंड स्मारक और धमनार के ऐतिहासिक समूह को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था। मध्यप्रदेश में अब यूनेस्को द्वारा घोषित 18 धरोहरें हैं। जिसमें से 3 स्थाई और 15 टेंटेटिव सूची में हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में प्रदेश के खजुराहो के मंदिर समूह, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थायी सूची में शामिल है। यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में मांडू में स्मारकों का समूह, ओरछा का ऐतिहासिक समूह, नर्मदा घाटी में भेड़ाघाट-लमेटाघाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और चंदेरी भी शामिल है। यह उपलब्धि हमारी धरोहरों के संरक्षण तथा संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिये एमपी टूरिज्म बोर्ड, संस्कृति विभाग, पुरातत्वविदों, इतिहास प्रेमियों, संस्थाओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मध्यप्रदेश को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नई ऊंचाइयां देगी, साथ ही हमारे गौरवशाली अतीत को नई पहचान दिलाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हम अपनी धरोहरों के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध रहें और मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक गरिमा को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।

माधव, कूनो और घड़ियाल अभयारण्य से चंबल में विकास के नए द्वार खुलेंगे

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी में नवनिर्मित 'माधव टाइगर रिजर्व' का शुभारंभ किया। यह मध्यप्रदेश का 9वां और देश का 58वां नेशनल टाइगर रिजर्व है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुनर्स्थापन प्रक्रिया से यहां लाई गई एक बाघिन को टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुक्त आवास में छोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर चंबल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। माधव टाइगर रिजर्व में बाघों का पुनर्स्थापन हो रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से राज्य को 9वें नेशनल टाइगर रिजर्व की अभूतपूर्व सौगात मिली है।

सिंहस्थ 2028 के लिए अभी से करें माइक्रो प्लानिंग, क्राउड मैनेजमेंट पर दें विशेष ध्यान

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में पूर्व में सम्पन्न हुए सिंहस्थ में प्राप्त अनुभवों को केन्द्र में रखते हुए सिंहस्थ 2028 के योजनाबद्ध आयोजन के संबंध में बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। लाखों-करोड़ों श्रद्धालु सिंहस्थ में उज्जैन आएंगे। किसी भी श्रद्धालु को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए जाएं। पुराने आयोजन से सीख लें और आगामी सिंहस्थ के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अभी से माइक्रो प्लानिंग कर व्यवस्थाओं को अंजाम देना प्रारंभ करें। सबसे बेहतर यह होगा कि सिंहस्थ की व्यवस्थाओं और प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य जून 2027 के पहले ही पूरे कर लिए जाएं। इससे रह गई कमी को दुरुस्त करने या व्यवस्थाओं को और भी अधिक बेहतर करने का समय भी मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ में लाखों-करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन शहर में आएंगे। बड़े मार्गों के अलावा उज्जैन शहर की अंदरूनी गलियों व रास्तों का भी और अधिक चौड़ीकरण करें ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन का वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध रहे और वे आसानी से आ-जा सकें।

जून 2027 तक पूरे किये जाएं कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ की व्यवस्थाओं एवं प्रबंधन के लिए मंजूर किए गए सभी कार्य जून 2027 तक पूरे कर लिए जाएं। चल रहे कार्यों की मासिक प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा की जाए। प्रबंधन में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। मंजूर किए गए सभी काम तय समय-सीमा में ही पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्री महाकाल लोक बनने के बाद प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की दिनों-दिन बढ़ती संख्या के अनुसार से ही सिंहस्थ की तैयारी की जाए, क्योंकि जो श्रद्धालु सिंहस्थ में आएंगे, वे बाबा महाकाल सहित अन्य देव स्थलों पर भी अवश्य ही जाएंगे। भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

8 मार्च

पीएफ खाते में बिना दस्तावेज दिए भी विवरण बदल सकेंगे

● कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार से लिंक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वाले सदस्यों को व्यक्तिगत विवरणों में महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वयं बिना दस्तावेज बदलने की अनुमति दे दी है। यदि यूएएन को पहले ही आधार के माध्यम से सत्यापित किया जा चुका है, तो अंशधारक अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता-माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति-पत्नी का नाम, सदस्यता ग्रहण करने की तिथि और सदस्यता छोड़ने की तिथि, बिना कोई दस्तावेज अपलोड किए अपडेट कर सकते हैं। नए प्रावधान के तहत अब नियोक्ता के माध्यम से विवरण में संशोधन करने का अनुरोध केवल उन्हीं अंशधारकों को करना होगा जिनका यूएएन एक अक्टूबर, 2017 से पहले जारी किया गया है।

● रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ को रोकने के लिए रेलवे ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं। महाकुंभ के दौरान तात्कालिक तौर पर देश भर के 60 प्रमुख स्टेशनों पर बनाए गए प्रतीक्षालय क्षेत्र को स्थायी किया जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के बारे में विमर्श किया गया। अब देश के 60 प्रमुख स्टेशनों के सभी अनाधिकृत प्रवेश प्वाइंट को सील कर दिया जाएगा। प्लेटफार्मों पर सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही जाने की अनुमति मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नई दिल्ली, आनंद विहार, सूरत, वाराणसी, अयोध्या एवं पटना स्टेशनों पर यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से शुरू की जा रही है। इसके साथ ही टिकटों की बिक्री ट्रेनों की क्षमता के अनुसार ही की जाएगी।

9 मार्च

लाभ पाने के लिए गिग वर्कर ई-श्रम पर पंजीकरण कराएं

● श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने गिग और मंच श्रमिकों से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए कहा है। इससे उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ मिल सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इस बजट में गिग वर्कर्स के लिए पीएम जन-आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा देने की पहल की गई है। योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये प्रति परिवार का उपचार उपलब्ध है।

● कनाडा ने देश में बिना किसी कार्य अनुभव के बसने के लिए नए होम केयर वर्कर इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की घोषणा की गई है। यह पायलट प्रोग्राम 31 मार्च, 2025 से शुरू होगा। प्रोग्राम के अंतर्गत होम केयर वर्कर के रूप में कनाडा में प्रवास करने के इच्छुक विदेशियों को कनाडा में कार्य अनुभव की आवश्यकता के बिना स्थायी निवास प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उन्हें केवल एक कनाडाई नियोक्ता से नौकरी की पेशकश की आवश्यकता होगी। इसके लिए श्रम बाजार पर प्रभाव का आकलन भी जरूरी नहीं माना गया है। योजना के अंतर्गत, कनाडा के इमिग्रेशन लेवल प्लान के हिस्से के रूप में कनाडा 15000 से अधिक देखभाल करने वालों को स्थायी निवासियों के रूप में स्वीकार करेगा।

10 मार्च

विश्व की पहली कमर्शियल निगरानी सैटेलाइट ने शुरू किया काम

● विश्व की पहली कमर्शियल निगरानी सैटेलाइट 'स्कॉट' ने काम शुरू कर दिया है।

यह अंतरिक्ष से पांच सेंटीमीटर से भी छोटी वस्तु का पता लगाने में सक्षम है। बेंगलुरु स्थित भारतीय स्टार्टअप 'दिगंतारा' ने 14 जनवरी को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर-12 रॉकेट से अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट (ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए स्पेस कैमरा) लॉन्च किया था। स्कॉट उपग्रह ने दक्षिणी अमरीका के ऊपर से गुजरते हुए पहली तस्वीर भेजी। दिगंतारा ने बताया कि अब अंतरिक्ष में छिपने की जगह खत्म हो गई है। स्कॉट को सूर्य-समकालिक कक्षा में तैनात किया गया है, जो इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उन वस्तुओं को मौजूदा सेंसरों की तुलना में अधिक दक्षता से ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। स्कॉट किसी भी मौसम और भौगोलिक स्थिति में काम कर सकता है।

● अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल स्कूलों में भी होने लगा है। ब्रिटेन में किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि एआई पर अधिक निर्भरता विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे उनकी सोचने की क्षमता पर असर पड़ने का खतरा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रौद्योगिकी से बच्चों के जीवन पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही ब्रिटेन में 13 से 18 वर्ष के चार में से तीन (77.1 प्रतिशत) बच्चे जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।

11 मार्च

एआईसीटीई ने टेक्निकल कॉलेजों के लिए ऑफलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जारी

● अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की एआईसीटीई ट्रेनिंग एंड लर्निंग (अटल) एकेडमी ने टेक्निकल कॉलेजों की फैकल्टी के लिए ऑफलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के दस्तावेज जारी कर दिए। इसके तहत कॉलेजों की फैकल्टी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स इसमें शामिल हो सकेंगे। इसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फैकल्टी को डोमेन नॉलेज के साथ ही उनकी स्किल को रियल लाइफ में कैसे एप्लाई करें इसकी क्षमता भी विकसित की जाएगी। शिक्षाविदों में नेतृत्व कौशल विकसित करने के साथ ही शिक्षकों की शिक्षण पद्धति और प्रभावशीलता में सुधार लाने पर ध्यान दिया जाएगा। ये प्रोग्राम इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, डिजाइन, होटल मैनेजमेंट, प्लानिंग और कम्प्यूटर एप्लिकेशन जैसे पारंपरिक और उभरते हुए क्षेत्रों में होंगे।

● संसद में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र ने बताया कि महाकुम्भ में संगम पर गंगा जल नहाने योग्य था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को तीन वर्षों में 7,421 करोड़ का आवंटन किया गया है।

12 मार्च

चंद्रयान-2 ने खोजे चंद्रमा के वातावरण में उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व

● चंद्रमा के वातावरण में आश्चर्यजनक रूप से उच्च इलेक्ट्रान घनत्व का पता चला है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वैज्ञानियों ने भारत के चंद्रयान-2 आर्बिटर से रेडियो संकेतों का विश्लेषण करते हुए पता लगाया कि चंद्रमा का आयनमंडल पृथ्वी की भू-चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय अप्रत्याशित रूप से उच्च इलेक्ट्रान घनत्व प्रदर्शित करता है। चंद्रयान-2 आर्बिटर अच्छे तरीके से काम कर रहा है और डाटा उपलब्ध करा रहा है। इसरो ने बयान में यह भी कहा कि इस खोज से पता चलता है कि चंद्रमा के वातावरण में प्लाज्मा किस प्रकार व्यवहार करता है।

● अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा के स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यह कदम ओंटारियो द्वारा अमेरिका को बिजली निर्यात पर 25 प्रतिशत अधिभार लगाने के प्रतिशोध में उठाया गया है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि कनाडा अमेरिकी ऊर्जा आपूर्ति को काटने के लिए तैयार है।

13 मार्च

वायुसेना को मिलेंगी 18 'अश्विनी' रडार

● रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के चल रहे अभियान के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 18 'अश्विनी' निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार (एलएलटीआर) की खरीद के लिए 2,906 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह पहली बार है कि भारतीय वायुसेना विदेश से आयात किए जाने वाले एलएलटीआर के बजाय स्वदेशी एलएलटीआर को शामिल करेगी। यह रडार लड़ाकू विमानों से लेकर मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) या ड्रोन और हेलिकॉप्टर

जैसे धीमी गति से चलने वाले उपकरणों तक को पहचानने में सक्षम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान ने इस रडार को विकसित किया है।

● क्यूएस विषयवार रैंकिंग 2025 जारी कर दी गई है। इसमें नौ भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने शीर्ष-50 में जगह बनाई है। इस सूची में तीन आईआईटी, दो आईआईएम और नई दिल्ली स्थित जेएनयू शामिल है। विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 15वें संस्करण के अनुसार, भारत के नौ संस्थानों ने विषय रैंकिंग और व्यापक संकाय क्षेत्रों में शीर्ष 50 में 12 स्थान हासिल किए। उल्लेखनीय है कि आईएसएम, धनबाद को इंजीनियरिंग-खनिज एवं खनन में विश्व स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी मुंबई और खड़गपुर को इंजीनियरिंग-खनिज और खनन के लिए 28वीं और 45वीं रैंकिंग दी गई है। आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे को 26वां पायदान मिला है। इसके साथ ही आईआईएम अहमदाबाद और बेंगलुरु को मैनेजमेंट अध्ययन में क्रमशः 27वां व 40वां स्थान मिला है।

14 मार्च

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रवेश के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

● दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के माध्यम से एडमिशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही एडमिशन बुलेटिन जारी कर दिया है। इस वर्ष डीयू के 73 स्नातक कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा। सबसे अधिक अंकों पर डीयू से एफिलिटेड कॉलेजों में छात्रों को दाखिला मिलता है। इस वर्ष बड़ा बदलाव यह है कि 12वीं के नॉन मैथेमेटिक्स स्टूडेंट्स भी बीकॉम ऑनर्स में दाखिला ले पाएंगे। उधर, बीकॉम मैथेमेटिक्स, कम्प्यूटर

साइंस और स्टेटेस्टिक्स के लिए 12वीं में मैथ्स होना जरूरी है, लेकिन लैंग्वेज कोर्सेज के आधार पर भी दाखिला दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए छात्रों को कॉमन सीट अलॉकेशन सिस्टम (सीएसएएस) से गुजरना होगा।

● देश में विमान बनाने की तैयारी चल रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय पांच वर्षों में देश का पहला रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट (आरटीए) बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक खास कंपनी (एसपीवी) बनाई जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि देश में एयरक्राफ्ट और इनके पुर्जे की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी नीतियां मौजूद हैं। बेंगलुरु स्थित सीएसआईआर-एनएएल में 19 सीटों वाले हल्के स्वदेशी परिवहन विमान सारस एमके 2 का विकास प्रगति पर है।

● केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में एलन मस्क की किफ़ायती सैटेलाइट इंटरनेट सेवा 'स्टारलिंक' का स्वागत किया। भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनी, एयरटेल एवं स्टारलिंक ने सेवाएं लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ साझेदारी की है। श्री वैष्णव ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों की रेलवे परियोजनाओं के लिए यह सेवाएं उपयोगी होंगी।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित
फोटो : गूगल से साभार)

एजेंसी देना है

मध्यप्रदेश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला साप्ताहिक समाचार पत्र

रोज़गार और निर्माण

प्रदेश के छिन्दवाड़ा, धार, रतलाम, राजगढ़ एवं नीमच में एजेंसी नियुक्त करना है।

एजेंसी संबंधित कार्य के लिए कार्यालयीन समय में संपर्क करें

0755-2760006

प्रमुख आकर्षण

- कैरियर की ख़बरें
- सप्ताह की प्रमुख घटनाएं
- सम-सामयिक विषयों पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां
- मध्यप्रदेश सरकार के निर्णयों और योजनाओं की जानकारियां
- खेल जगत की उल्लेखनीय ख़बरें
- विज्ञान की बात

मध्यप्रदेश माध्यम

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
www.mpmadhyam.in
madhyam.rojgar@gmail.com

आज ही खरीदें प्रमुख बुक-स्टॉलों पर उपलब्ध

वर्ष 42, अंक 12 17.03.2025 से 23.03.2025

रोज़गार और निर्माण

www rojgaraurnirman.in

- प्रबंध संचालक - डॉ. सुदाम खाड़े
- सम्पादक - रंजना चितले
- प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- प्रबंधक - सुधाष चन्द्र सेठी (मुद्रण)
- आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
- वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इसे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध मध्यप्रदेश सरकार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी हैं। सशक्त नारी से ही प्रदेश और देश न केवल सशक्त बन रहा है, बल्कि समृद्ध भी हो रहा है। महिलाओं को अधिकार देने से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। भारत विश्व का एक मात्र ऐसा देश है जो अनादिकाल से मातृशक्ति का सम्मान करता रहा है। सनातन संस्कृति में शक्ति, धन आदि को देवियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। अगले लोकसभा चुनाव के बाद संसद में महिलाओं को मिले 33 प्रतिशत आरक्षण की शक्ति परिलक्षित होगी और देश का संचालन महिलाओं के हाथों में होगा। नारी सशक्तिकरण के लिये प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में भी एक प्रतिशत की छूट दी गई है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सम्पत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम पर हो रहा है। प्रदेश में 44 फीसदी स्टार्ट-अप महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों की संख्या 5 लाख से अधिक है। महिलाओं को उद्योग स्थापना के लिए बैंक लोन में अनुदान भी दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश सरकार बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक करोड़ 27 लाख बहनों के खाते में 1552.73 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। पिछले एक वर्ष जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक लाड़ली बहनों के खाते में 22 हजार 227.89 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। हर महीने लाड़ली बहनों के खाते में राशि भेजी जाती है। मुख्यमंत्री ने बहनों को आश्वस्त किया कि लाड़ली बहना योजना कभी नहीं रुकेगी, राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। नारी सशक्तिकरण के लिए प्रदेश से आरंभ की गई इस योजना का देशभर में अभिनंदन हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना में 29 लाख बहनों को 55 करोड़ 95 लाख की अनुदान राशि सिलेंडर रीफिलिंग के लिए अंतरित की गई है। अब तक 825 करोड़ रुपये की राशि बहनों को जारी की जा चुकी है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अंतर्गत जारी राशि से महिलाओं को प्रतिदिन ईंधन जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। नारी सशक्तिकरण के लिए चल रहे अभियान में यह गतिविधियां महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ज्ञान पर ध्यान के अंतर्गत गरीब, युवा, किसान सहित नारी सशक्तिकरण के लिए जारी विशेष प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो कह रही है वह करके दिखा रही है। जब हम विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को पूरा करेंगे तो इसमें मध्यप्रदेश का योगदान अहम होगा और राज्य देश में नंबर-1 बन चुका होगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 19 हजार से अधिक बहनों का कन्यादन सरकार की ओर से किया गया है। योजना में हो रहे सामुहिक विवाह सामाजिक समरसता, सौहार्द और एकता का संदेश दे रहे हैं। यह अभियान पवित्रता का संकल्प है, जिसमें अब तक 115 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। आहार अनुदान योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के माध्यम से बहनों को सहायता प्रदान करते हुए समर्थ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में देश में चार करोड़ से अधिक मकान बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में लागू इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चियों, बालिकाओं, बेटियों के साथ दुराचार करने वालों के विरुद्ध सरकार कठोरतम कदम उठायेगी। दोषियों को फांसी की सजा भी दिलवायेंगे। किसी भी दोषी को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। मध्यप्रदेश में जोर जबरदस्ती या बहला फुसलाकर विवाह और धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिये धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू है। राज्य सरकार ने शासकीय महिला कर्मचारियों को सात दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश और संविदा कर्मचारी बहनों को 180 दिवस का प्रसूति अवकाश देने की व्यवस्था की है। राज्य सरकार हर कदम पर बहनों के साथ है, वे आगे बढ़ें, सरकार उन्हें हर संभव सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगी।

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चीनी हैकर्स के समूहों की जानकारी का किया खुलासा

चीन के जासूसों द्वारा नेटवर्क बनाकर की जा रही जासूसी की जानकारी अमेरिका के वैज्ञानिकों के समूह ने निकाल ली है। वैज्ञानिकों ने चीन के हैकर्स के एक बड़े समूह की जानकारी प्राप्त की है जो अमेरिका सहित कई बड़े देशों की गोपनीय जानकारियों को चुराने की योजना पर काम कर रहे थे। जब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस समूह की जानकारी को सार्वजनिक किया तो यह जानने के बाद यूके, कनाडा समेत कई अन्य देशों ने चीन के जासूस नेटवर्क पर चिंता जताई और अपना विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि चीन को एक ऐसी डिवाइस मिल गई है जिससे चीन पूरी दुनिया पर नजर रख सकने में सक्षम हो गया है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार चीन के वैज्ञानिकों ने एक नया सैटेलाइट विकसित किया है जो लेजर-इमेजिंग तकनीक से 100 किलोमीटर दूर मौजूद व्यक्ति के चेहरे की पहचान करने में सक्षम है। यह तकनीक मौजूदा स्पाई कैमरों और टेलीस्कोप की तुलना में 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह नई तकनीक सिंथेटिक एपर्चर लिडार (एसएएल) पर आधारित है। एसएएल टेक्नोलॉजी की खासियत है कि यह ऑब्जेक्ट की मूवमेंट का इस्तेमाल करके हाई-रिजॉल्यूशन इमेज बनाती है। यह लेजर रेडार की तरह काम करता है और 2D व 3D इमेजिंग में सक्षम है। पहले के एसएआर सिस्टम माइक्रोवेव रेडिएशन पर आधारित थे, जिनकी वेवलेंथ लंबी होती थी और इमेज की क्वालिटी सीमित रहती थी। लेकिन एसएएल ऑप्टिकल वेवलेंथ पर काम करता है, जिससे पहले से कहीं ज्यादा शार्प और हाई-रिजॉल्यूशन इमेज मिलती हैं।

वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को चीन के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित किंगहाई झील के पास टेस्ट किया। सिस्टम ने 101.8 किलोमीटर की दूरी पर रखे रिफ्लेक्टिव प्रिज्म्स को स्कैन किया। यह 1.7 मिलिमीटर तक की छोटी डिटेल्स को पहचान सका। वर्ष 2011 में लॉकहीड मार्टिन के एक सिस्टम ने 1.6 किलोमीटर की दूरी से सटीकता हासिल की थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक तेज हवा, कोहरा, बारिश या बादल भी इस तकनीक की सटीकता को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। यह तकनीक जासूसी उपग्रहों, अंतरिक्ष निगरानी और हाई-रिजॉल्यूशन मैपिंग में बड़ा बदलाव ला सकती है।

- विकास तिवारी
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर लेखन करते हैं)

'मोदी-मंत्रों' के साथ विकसित मध्यप्रदेश की ऊंची उड़ान का बजट

डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में काम कर रही मध्यप्रदेश सरकार का यह बजट बहुआयामी है। इसमें विकसित मध्यप्रदेश की रूपरेखा के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीनों मंत्र की झलक है। मोदी जी के यह तीन मंत्र 'विकास के साथ विरासत' 'Gyan का सम्मान' और 'लोकल फॉर वोकल' हैं। बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के साथ, विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के प्रावधान भी है। बिना कोई नया कर लगाये 15 प्रतिशत की वृद्धि बजट की सबसे बड़ी विशेषता है।

वर्ष 2025-26 के लिये मध्यप्रदेश सरकार का बजट आ गया है। विशेषताओं, व्यापकताओं और नवाचारों से युक्त है। यह बजट 12 मार्च को वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में प्रस्तुत किया। बजट में एक ओर मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सहेजा गया है तो दूसरी ओर आधुनिक दुनिया की दौड़ में अग्रणी रहने के लिये औद्योगिकरण को गति देने का प्रयास किया गया है, ताकि मध्यप्रदेश भारत के विकसित प्रातों में अग्रणी बन सके। बजट परिवार का हो या किसी स्वायत्तशासी संस्थान का अथवा किसी प्रगतिशील राष्ट्र का उसमें अतीत के अनुभव, आधारभूत आयामों का सशक्तिकरण, आय वृद्धि के उपाय और व्यय का नियमन होना चाहिए। इसके साथ एक गतिमान वातावरण भी होना चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार का यह बजट इन आधारभूत आवश्यकताओं के अनुरूप है। यह अनेक विशेषताओं, व्यापकताओं और नवाचारों से युक्त है। बजट में किसी भी पुरानी योजना को बंद नहीं किया गया है और न कोई नया टैक्स लगाया गया है। किसी पुराने टैक्स में वृद्धि भी नहीं की गई।

विरासत के साथ विकास

किसी भी परिवार, समाज और देश की अपनी विरासत होती है। उसमें विशेषताओं और वर्जनाओं दोनों की झलक होती है। विरासत और इतिहास वर्तमान पीढ़ी को अपनी विकास यात्रा में गतिमान बनाता है। विरासत में अनेक कथानक भी जुड़े होते हैं। इन कथानकों में उन्नति का संदेश और अवनति के प्रति सावधानी भी होती है। मध्यप्रदेश में ऐसे अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक स्थल हैं, जो गौरवशाली अतीत के प्रसंगों से जुड़े हैं। मध्यप्रदेश सरकार के इस बजट में उन सभी स्थानों के विकास को महत्व दिया गया है। जिससे पर्यटन बढ़ेगा और मध्यप्रदेश की विशिष्ट पहचान संसार के सामने आ सकेगी। इससे एक तीसरा लाभ भी है, जो प्रदेश की वर्तमान पीढ़ी में एक विशिष्ट आत्मविश्वास का संचार करेगा। वही पौधा विशाल वृक्ष बनकर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। यदि जड़ें कमजोर हैं, तो वृक्ष पहली बरसाती बाढ़ में ही बह जायेगा। इसलिये जड़ों का गहरा और मजबूत होना जरूरी है। यही सिद्धांत समाज और राष्ट्र के दीर्घजीवन पर भी लागू होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत यात्रा को विरासत से जोड़ा है। जिसे मध्यप्रदेश सरकार ने भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रांत है। यह संसार के प्राचीनतम् भू-भागों में से एक है। अरावली, सतपुड़ा और विन्ध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से समृद्ध यह भू-भाग तब भी था, जब यूरोप ने आकार भी नहीं लिया था। यहां करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म और लाखों वर्ष पुराने शैलचित्र मिलते हैं। डायनासोर के जीवाश्म भी मध्यप्रदेश में मिले हैं। डॉ मोहन सरकार के इस बजट में इन सभी विशिष्ट स्थलों को सहेजने का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व विभाग में 1610 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत दो जीवाश्म पार्क विकसित किये जायेंगे। इनमें करोड़ों वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म सहित वे सभी 'फॉसिल्स' सहेजे जायेंगे जो आज भी पूरे विश्व के लिये कौतूहल हैं। फॉसिल्स पार्क विकसित हो जाने से संसार भर के शोधकर्ता मध्यप्रदेश आयेंगे। इससे प्रदेश की साख पूरे संसार में बढ़ेगी और स्थानीय नागरिकों को रोजगार के परोक्ष अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ ओंकारेश्वर, महाकाल उज्जैन, मैहर जैसे धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के प्रावधान किये गये हैं। बजट में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिये दो हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर मध्यप्रदेश सरकार सावधान हुई है। बजट में महाकाल लोक की भांति ओंकारेश्वर महालोक विकसित करने का प्रावधान है। ओंकारेश्वर आदि शंकराचार्य जी की तपोस्थली भी रही है। यहां आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान की स्थापना की जा रही है। इसके लिये पांच सौ करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। त्रेतायुग में भगवान श्रीराम अपनी वनयात्रा में मध्यप्रदेश भी आये थे। चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक उनकी यात्रा के चिह्न हैं। बजट में राम वन पथ गमन के विकास के लिये तीस करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं महाभारतकाल में भगवान श्रीकृष्ण की यात्रा चिह्नों को समेटने के लिये श्रीकृष्ण पाथेय योजना पर दस करोड़ रुपये का प्रावधान है। इनके अतिरिक्त धार्मिक और सांस्कृतिक अन्य 14 स्मारकों को सहेजने के लिये बजट में 507 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार इन सभी स्थलों पर अधोसंरचना के विकास के साथ पर्यटन प्रोत्साहन की योजना पर काम कर रही है। इससे दो लाभ होंगे एक तो पर्यटन से स्थानीय नागरिकों को परोक्ष रोजगार मिलेगा और दूसरा मध्यप्रदेश की विरासत संसार के सामने आ सकेगी। इन सभी स्थलों पर धार्मिक ग्रंथों, साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अध्ययन केन्द्र भी स्थापित किये जायेंगे। इस मद पर सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के इस बजट में यदि अपनी विरासत सहेजने का प्रावधान किया गया है, तो आधुनिक विकास यात्रा के लिये औद्योगिकरण पर भी जोर दिया है। यह पूरा वर्ष उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। बजट में 39 नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की गई है। निवेश अनुदान के लंबित प्रकरण के निराकरण के लिये बजट प्रावधान भी बढ़ाया है। इन निर्णयों से मध्यप्रदेश के औद्योगीकरण की गति बढ़ेगी। विशेषकर उद्योग वर्ष मनाने की घोषणा से स्थानीय नागरिकों में उद्योग स्थापना के प्रति रुचि जाग्रत होगी। वे अपनी रुचि, प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप अपना उद्योग व्यापार स्थापित करने की ओर प्रोत्साहित होंगे। मध्यप्रदेश सरकार की यह नीति आधुनिक दुनिया की प्रगति दौड़ में प्रदेश और देश को अग्रणी बनने के लिये महत्वपूर्ण है।

आज की दुनियां में विकास की दौड़ की बुनियाद औद्योगीकरण है। औद्योगीकरण की मानों एक स्पर्धा चल रही है। इसमें अग्रणी रहने के लिये औद्योगीकरण में नवाचार जरूरी है। इन नवाचारों के लिये ही पहले मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स समिट और बाद में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन हुये। बजट के इन प्रावधानों से इन नवाचारों को गति मिलेगी। इसीलिए मध्यप्रदेश सरकार ने अपने बजट में 'विरासतों को सहेजने के साथ औद्योगिक विकास के भी प्रावधान किये हैं। विरासत सहेजने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और औद्योगिक योजनाओं से आधुनिक विकास को गति मिलेगी।

लोकल फॉर वोकल के साथ प्रगति की यात्रा

वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने प्रत्येक जिले के अपने विशिष्ट उत्पाद को प्रोत्साहित करने की घोषणा की है। उन्होंने लघु कुटीर और मध्यम उद्योगों को भूमि आवंटन, अनुदान और उत्पाद विक्रय को प्रोत्साहित करने की घोषणा भी की है। मध्यप्रदेश सरकार के इस बजट में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत को सहेजने के साथ प्राकृतिक विशेषताओं को भी संसार के सामने लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषता होती है। इसे उस क्षेत्र के निवासियों के शिल्प कौशल, उत्पाद, फसलों एवं फलों की विशिष्टता से समझा जा सकता है। इस बजट में प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है। उस विशिष्ट उत्पाद से प्रत्येक जिले की विशेष पहचान वैश्विक होगी, वैश्विक मार्केट मिलेगा।

बजट में गरीब, महिला, किसान और युवाओं को सशक्त बनाने के प्रावधान

भारत की पहचान उसके कला-कौशल, प्रतिभा और श्रम साधना से रही है। समृद्धि का केन्द्र युवा, महिलाएं और किसान रहे हैं। भारत की महिलाएं कृषि कार्य और शिल्प कौशल दोनों में बराबरी से सहभागी रही हैं। लेकिन मध्यकाल के दमन और शोषण से स्थिति विपरीत हो गई। इससे गरीबी के रूप में नया वर्ग सामने आया। समाज और राष्ट्र की विकास यात्रा में गरीबी सबसे बड़ी बाधक होती है। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने बजट में इन दोनों दिशाओं में प्रावधान किये हैं। एक ओर गरीबी उन्मूलन के लिये अपना खजाना खोला है। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1.33 करोड़ परिवारों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है और दूसरी ओर युवा, महिला और किसानों के सशक्तिकरण की योजनाओं पर भी फोकस किया है। बजट में पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 19 हजार 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने धान खरीदी में किसानों को समर्थन मूल्य पर अनुदान बढ़ाया है। किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिये पशुपालन के लिये प्रोत्साहित किया है। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण के समापन में कहा कि- आंकड़े नहीं, विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा है' इस पंक्ति में मध्यप्रदेश के विकास और भविष्य की यात्रा का संकल्प है। यह बजट कहने के लिये एक वर्ष का आय-व्यय है, लेकिन इसमें विकसित प्रांतों में मध्यप्रदेश को अग्रणी बनाने का प्रारूप भी है।

रमेश शर्मा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रं. 1 ग्वालियर

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 24/टीसी/डी-1/ ग्वा./2024-25 **दिनांक : 24.02.2025**

निविदा विज्ञप्ति सूचना

म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से म.प्र. की ओर से निम्नांकित कार्यों हेतु सड़क/भवन दिनांक 25.03.2022/01.01.2024 तथा निविदा सूचना जारी होने तक उसमें किये गये संशोधन सहित मोहरबन्द निविदायें नवीन निविदा फार्म 2.10 में आमंत्रित की जाती है, प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यालय में निविदायें डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्राप्त की जावेंगी। पोस्टल विलम्ब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र की राशि एवं फार्म	1. ठेके की अनुमानित लागत (लाख में) 2. अमानत राशि	कौर निविदा प्रपत्र विक्रय का समय एवं दिनांक	1. निविदा प्राप्ति का दिनांक 2. कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. स.क्र. 1	1. निविदा खोलने का दिनांक 2. कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. स.क्र. 1	1. कार्य पूर्ण करने की अवधि 2. ठेकेदार की श्रेणी 3. आमंत्रण क्र.
1.	Additional And Altration And Renovation Work in Cottage Judges Court Yard And Kitchen At New High Court Campus Gwalior Under H.Q. 2 Sub Division Gwalior.	2000/-	9.99 20,000/-	19.03.25	21.03.25	21.03.25	एक माह केंद्रीयकृत प्रथम आमंत्रण
2.	Renovation Work in Cash Section At New High Court Gwalior Under H.Q. 2 Sub Division Gwalior.	2000/-	9.99 20000/-	19.03.25	21.03.25	21.03.25	एक माह केंद्रीयकृत प्रथम आमंत्रण
3.	R.R.I. Hose Pipe, Hose Red And Other Fitting For Fire System At New High Court Gwalior Under H.Q. 2 Sub Division Gwalior.	2000/-	9.99 20000/-	19.03.25	21.03.25	21.03.25	एक माह केंद्रीयकृत प्रथम आमंत्रण
4.	Renovation Work in Filing Section At At New High Court Gwalior Under H.Q. 2 Sub Division Gwalior.	2000/-	9.99 20000/-	19.03.25	21.03.25	21.03.25	एक माह केंद्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

कुल कार्य - 04, कुल अनुमानित लागत कुल राशि रु. 39.96 लाख
टीप :- शेष शर्तें कार्यालयीन समय पर कार्यालय में देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री
जी- 24283/50669/2025 लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1, ग्वालियर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन), लोक निर्माण विभाग, कोठी रोड, सिविल लाइंस, सीधी (म.प्र.)

Phone No. : 07822-297539, E-mail : piusidhi@gmail.com

एन.आई.टी. नं.-07/2025/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/सीई/पी.डब्ल्यू.डी./भवन/690 **रीवा, दिनांक : 06.03.2025**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है:-

स. क्र.	पोर्टल टेण्डर क्र.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पी.ए.सी.) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ई.एम.डी.) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	90 प्रतिशत अविवादित भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित
1.	2025_PWPIU_ 408252_1	जिला सीधी अन्तर्गत प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुसमी जिला सीधी में 50 सीटर बालक एवं 50 सीटर बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य सह जल प्रदाय, सेनेटरी फिटिंग एवं विद्युतीकरण कार्य (प्रथम आमंत्रण)	सीधी	367.17	367170/-	15000/-	12 माह	हां

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 10.03.2025 समय 10:00 से दिनांक 24.03.2025 समय 18:00 तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

जी-24287/50670/2025 कार्यपालन यंत्री (भवन) लोक निर्माण विभाग, सीधी

संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश

गुरू तेग बहादुर काम्प्लेक्स, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर, भोपाल- 462003
दूरभाष : 0755-2553743, e-mail : dswoffice@mp.gov.in, https//sainikkalyan.mp.gov.in

प्रेस नोट/विज्ञप्ति

संचालनालय सैनिक कल्याण म.प्र. पहली मंजिल, जीटीबी कॉम्प्लेक्स, टीटी नगर, न्यू मार्केट भोपाल-462003 में 01 अस्थायी सुरक्षाकर्मी कलेक्टर दरों पर नियुक्त किया जाना है। उक्त संबंध में केवल इच्छुक भूतपूर्व सैनिक **दिनांक 20 मार्च, 2025 तक** अपना बायोडाटा एवं स्वप्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रति मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति, शाखा भोपाल अथवा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बाणगंगा चौराहा भोपाल में जमा करें।

जी-24309/50673/2025 प्रशासनिक - सह - लेखा अधिकारी वास्ते संचालक

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल (म.प्र.)

निविदा सूचना क्रमांक 26/मु.अ. (सेतु परिक्षेत्र)/वर्ष 2024-25 **भोपाल, दिनांक : 10.03.2025**

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	ई.एम.डी. राशि एवं टेण्डर फीस तथा निविदा से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज जमा करने हेतु
1.	2025_ PWDRB_ 408592_1	उज्जैन	पुल कार्य	उज्जैन जिले के अतंर्गत तपोभूमि से हामूखेड़ी मार्ग में क्षिप्रा नदी पर पहुँचमार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	प्रथम	1727.67	केवल ऑनलाइन
2.	2025_ PWDRB_ 408593_1	खण्डवा	पुल कार्य	खण्डवा जिले में बीड शाहपुरा पिपलानी मार्ग के कि.मी. 19/4 में रूपारेल नदी पर पहुँचमार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य	प्रथम	1302.70	केवल ऑनलाइन
3.	2025_ PWDRB_ 408594_1	बैतूल	पुल कार्य	बैतूल जिले के खेड़ीमार्ग में माचना नदी पर पहुँचमार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।	प्रथम	1083.59	केवल ऑनलाइन
				कुल योग		**4113.96**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 01.04.2025 (17:30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

जी-24331/50674/2025 मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण परिक्षेत्र, भोपाल

REQUIREMENT FOR OUR PRESTIGIOUS INSTITUTIONS

1. **Compfeeders AISECT College of Professional Studies,** Indore
2. **Madhuban Institute of Professional Studies,** Indore
3. **Compfeeder Takniki Prashikshan Sanstha,** Indore
4. **Madhuban College of Law (Proposed),** Indore

COMP-FEEDERS GROUP OF INSTITUTIONS —INDORE/BARWANI—

Affiliated to: **DAVV Indore** | Approved by: • **AICTE / NCTE New Delhi** • **Higher Education Govt. of M.P. Bhopal**

PRINCIPAL PROFESSOR **ASSOCIATE PROFESSOR** **ASSISTANT PROFESSOR**

Qualification as per AICTE / NCTE / DAVV / KTBU under Code 28 Norms.

1. **Madhuban College of Management,** Barwani
2. **Madhuban College of Education,** Barwani

Affiliated to: **KTBU Khargone** | Approved by: • **AICTE / NCTE New Delhi** • **Higher Education Govt. of M.P Bhopal**

Faculty of: **All Subjects of Management, Commerce, Hindi, English, Computer, Political Science, History, Sociology, Economics, Law, Education.**

Non-Teaching: **CEO • PA to Chairman, TPO, Accountant, Computer Operator, Librarian, Sports Officer, Counselor, Marketing Executive, Lab Tech. / Admin. Staff also required.**

Qualification & Salary as per norms for qualified & eligible candidates.

Send CV along with all Xerox testimonials with 2 Photo & mention highlighted city & post name (apply for) by **email to : madhuban123@gmail.com**

Indore Campus: **RR CAT, Rau Road, Indore (M.P)**
Barwani Campus: **Kukshi Bypass Road, Barwani (M.P)**

VOLUNTARY

R-50677/2025

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
ई-मेल:- eervskvv@gmail.com फोन: 0751-2467680

क्र./जनसं/रा.यं./2025/4363 **दिनांक : 11-03-2025**

// प्रेस विज्ञप्ति //

निविदा सूचना No./E.E./2025/Gwalior/4363 date 11-03-2025 रा.वि.सि.कृ.वि. ग्वालियर के अंतर्गत विद्युत कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा Annual Maintenance contract AMC for Lifts (6 Nos) at New Campus RVSKVV, Gwalior (2025_RVSKV_408933_1) आमंत्रित की गई है। निविदा की ऑनलाइन क्रय की अंतिम तिथि 25.03.2025 को सायं 05:30 तक है। विस्तृत निविदा सूचना वि.वि. वेबसाइट एवं पोर्टल **https:www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर

R-50668/2025

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र. 1, जबलपुर

निविदा सूचना क्र 34 वर्ष 2024-25 टेण्डर लिपिक

जबलपुर, दिनांक : 12.03.2025

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों की निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। कार्यों का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्र.	ई-टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ईएमडी, टेण्डर फीस एवं निविदा से संबंधित अन्य अभिलेख जमा करने हेतु
1.	2025_PWDRB_409209_pack 1	देवनगर सिहोदा अभाना मार्ग के कि.मी. 1, 2, 5 कुल 3.00 किमी एवं रानीताल रूपनाथ मार्ग के कि.मी. 15 से 21/4 कुल लंबाई 6.20 किमी में बी.टी. नवीनीकरण का कार्य।	प्रथम	127.03	127030	12500	06 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
2.	2025_PWDRB_409213_pack1	दऊरा कटरा दोहतारा बमहोरी मारूद मार्ग के कि.मी. 1 से 9 कुल 9.00 किमी एवं बनकेडी पोनिया ककरहटा मार्ग के किमी 1 से 4 कुल लंबाई 13.00 में बी.टी. नवीनीकरण का कार्य।	प्रथम	179.99	179990	12500	06 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
3.	2025_PWDRB_409214_pack 1	बुढ़ागर कैलवास कंजई मार्ग के किमी 1 कुल 0.60 किमी एवं किमी 4.60 कुल 2.00 किमी, मोहानिया पहुंच मार्ग के किमी 1 कुल 1.00 किमी, सिंगलदीप से मुडिया निरंदपुर मार्ग के किमी 1,2,3 कुल 3.00 किमी एवं इद्राना गनियारी मुर्ई मार्ग के किमी 12 कुल 2.00 किमी कुल लंबाई 8.40 किमी में बी.टी. नवीनीकरण का कार्य।	प्रथम	93.38	93380	10000	04 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
4.	2025_PWDRB_409215_pack1	कुण्डम कुण्डेश्वर मार्ग लंबाई 2.00 किमी, जैतपुरी से सरसवा मार्ग लंबाई 2.60 कि.मी. एवं तिलसानी बघराजी मार्ग लंबाई 5.00 किमी में बी. टी. नवीनीकरण का कार्य।	प्रथम	113.73	113730	12500	06 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
5.	2025_PWDRB_409219_pack1	बम्हनी पहुंच मार्ग लंबाई 1.18 किमी, धनपुरी पडवार इमलई मार्ग लंबाई 7.00 किमी में बी.टी. नवीनीकरण का कार्य।	प्रथम	112.00	112000	12500	06 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
6.	2025_PWDRB_409222_pack1	धनपुरी पडवार इमलई मार्ग के किमी 12 से 22 कुल 10.00 किमी में माइक्रो सर्फेसिंग का कार्य।	प्रथम	85.73	85730	10000	04 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
7.	2025_PWDRB_409225_pack1	सारा से सुरैया मार्ग लंबाई 2.10 किमी एवं भीटा खुर्द से लमकना मार्ग लंबाई 1.10 किमी का निर्माण कार्य।	प्रथम	228.22	228220	15000	08 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
8.	2025_PWDRB_409226_pack1	मुख्यालय उपसंभाग क्र. 2, जबलपुर अंतर्गत रांझी रोड सेक्शन के विभिन्न मार्गों में बी. टी. पेंच मरम्मत का कार्य।	प्रथम	9.00	18000	2000	03 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
9.	2025_PWDRB_409227_pack1	महगवां परियट झुरझुरू मार्ग व्हाया लिलखेड़ा लंबाई 3.00 किमी का निर्माण कार्य।	प्रथम	351.62	351620	15000	10 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
10.	2025_PWDRB_409229_pack1	तिलगवां से छितरी मार्ग का निर्माण कार्य।	प्रथम	224.89	225000	15000	06 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
11.	2025_PWDRB_409233_pack1	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय गेट से जबलपुर एयरपोर्ट मार्ग कुल लंबाई 10.10 कि.मी. प्राक्कलन लंबाई 2.90 किमी में माइक्रो सर्फेसिंग का कार्य।	प्रथम	49.34	50000	5000	04 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
12.	2025_PWDRB_409237_pack1	मुख्यालय उपसंभाग क्र. 1, जबलपुर अंतर्गत मझौली सेक्शन के विभिन्न मार्गों में बी.टी. पेंच मरम्मत का कार्य।	प्रथम	10.00	20000	2000	03 माह वर्षा ऋतु सहित	केवल ऑनलाइन
		कुल योग		1584.93				

टीप :- (1) निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 24.03.2025, 17.30 बजे तक** है। अन्य तिथियाँ एवं विस्तृत विवरण व संशोधन ऑनलाइन वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार के संशोधन का पुनः प्रकाशन नहीं कराया जावेगा। संशोधन सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री

जी-24305/50672/2025

लोक निर्माण विभाग (भ/स), सभाग संभाग क्र 1 जबलपुर

कार्यालय मुख्य अभियंता (भवन)
लोक निर्माण विभाग ओल्ड पलासिया इन्दौर (म. प्र.)

ई-मेल : apdpiuindore@gmail.com, फैक्स : 0731-4989768

क्र. एफ-3/सामान्य/निविदा प्रकाशन/मु.अ. (भवन) इन्दौर/2025/एनआईटी-28/676

इन्दौर दिनांक : 13.03.2025

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 28/2025

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग, परिक्षेत्र इन्दौर के अंतर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीयन ठेकेदार से लोक निर्माण विभाग, म.प्र. द्वारा दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील एस.ओ.आर. एवं निविदा सूचना प्रकाशन तिथि संशोधित, निर्धारित तिथि (Key-Date) अनुसार के आधार पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र.	पोर्टल टेंडर क्र.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) मूल्य (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्यपूर्ण करने का समय (माह वर्षाकाल सहित)
1.	2025_PWPIU_406730_1	लोक निर्माण विभाग (भवन) अलीराजपुर के अंतर्गत छुटे हुये, मरम्मत मायनर एवं परफार्मेंस ग्यारंटी के तहत विभिन्न भवनों के निर्माण/ उन्नयन कार्य।	अलीराजपुर	1500/-	1,50,000	12,500	12
2.	2025_PWPIU_408683 1	राजस्व विभाग के तहत स्वीकृत निर्माण कार्य 1. Composite Office Building for SDM/SDO Tehsil Sub Registrar Patwari Sub-Treasury at Pandhana, 2. Composite Tehsil Office Building at Mundi & Killod, 3. SDM/SDO Office Building at Khalwa, 4. Sub Tehsil (Tappa) Office Building at Jawar In District Khandwa फर्नीचर प्रदान एवं लगाने का कार्य।	खण्डवा	322.69	3,22,690	15,000	6
3.	2025_PWPIU_408686_1	शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय भवन जिला इन्दौर का निर्माण कार्य।	इन्दौर	3175.67	15,87,837	50,000	24
4.	2025_PWPIU_408603_1	लोक निर्माण विभाग (भवन) झाबुआ के अंतर्गत छुटे हुये, मरम्मत मायनर एवं परफार्मेंस ग्यारंटी के तहत विभिन्न भवनों के निर्माण/ उन्नयन कार्य।	झाबुआ	150.00	1,50,000	12,500	12

निविदा संबंधित तिथियां (Key - Date) :-

1. प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभिक तिथि : 11.03.2025
2. बिड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि : 13.03.2025
3. बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 27.03.2025
4. बिड खोलने की तिथि : 01.04.2025

जी-24336/50676/2025

मुख्य अभियंता (भवन) लो.नि.वि. परिक्षेत्र, इंदौर

कार्यालय संचालक, राज्य स्तरीय रोज़गार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण) पुलिस रेडियो मुख्यालय के सामने, भदभदा रोड, भोपाल

विज्ञप्ति

आवेदन की अंतिम तिथि : 02.04.225

प्रदेश के पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर युवक-युवतियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का 2 माह 15 दिवस की अवधि का निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पात्र एवं योग्य आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन प्रवेश हेतु नियम, शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट **www.bcwelfare.mp.nic.in** पर उपलब्ध हैं।

संचालक
राज्य स्तरीय रोज. एवं प्रशि. केंद्र
जी-24244/50665/2025 **(पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.क.), भोपाल, दूरभाष - (0755)2763284**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.1 ग्वालियर

निविदा विज्ञप्ति सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 23/टीसी/डी-1/ग्वा/2024-25 **दिनांक : 17.02.2025**

म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से म.प्र. की ओर से निम्नांकित कार्यों हेतु सड़क/भवन दिनांक 25.03.2022/01.01.2024 तथा निविदा सूचना जारी होने तक उसमें किये गये संशोधन सहित मोहरबंद निविदायें नवीन निविदा फार्म 2.10 में आमंत्रित की जाती है, प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यालय में निविदायें डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्राप्त की जावेगी। पोस्टल विलंब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. Renovation and Altration For Door, Window And Other Misc. Work At Hon'ble Chief Justice Bunglow No. 16A Gandhi Road Under H.Q.1 Sub Division Gwalior.

निविदा प्रपत्र की राशि एवं फार्म	1. ठेके की अनुमानित लागत (लाख में) 2. अमानत राशि	कोरे निविदा प्रपत्र विक्रय का समय एवं दिनांक	1. निविदा प्राप्ति का दिनांक 2. कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. स.क्र.1	1. निविदा खोलने का दिनांक 2. कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. स.क्र.1	1. कार्य पूर्ण करने की अवधि 2. ठेकेदार की श्रेणी 3. आमंत्रण क्र.
2000/-	9.98 20000/-	17.03.25	19.03.25	19.3.25	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. Construction of Guard Room At Hon'ble Chief Jusitce Bunglow No. 16A Gandhi Road Under H.Q.1 Sub Division Gwalior.

2000/-	9.98 20000/-	17.03.25	19.03.25	19.3.25	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. Renovation Work of Muduler Kichen At Hon'ble Chief Justice Bunglow No. 16A Gandhi Road Under H.Q.1 Sub Division Gwalior.

2000/-	9.98 20000/-	17.03.25	19.03.25	19.3.25	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. Renovation Work of T-Club of Hon'ble High Court Judges Chamber At New High Court Campus Under H.Q.2 Sub Division Gwalior.

2000/-	9.98 20000/-	17.03.25	19.03.25	19.3.25	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

कुल कार्य - 4 कुल अनुमानित लागत कुल राशि रु. 39.92 लाख
टीप - शेष शर्तें कार्यालयीन समय पर कार्यालय में देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री
जी-24153/50662/2025 **लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1 ग्वालियर**

कार्यालय मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र सागर

फोन नं. : 07582-220840, ईमेल आईडी : cepwdsagar@nic.in

एनआईटी नं. - 16/2024-25/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण **सागर, दिनांक : 07.03.2025**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :–

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. लोक निर्माण विभाग उपसंभाग रहली के अंतर्गत विभिन्न मार्गों का निर्माण कार्य लं. 4.50 कि.मी. अनु. लागत 648.87 लाख 1. रहली हरदौल से ढोंढा मार्ग का निर्माण कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित लं. 3.40 कि.मी. अनुमानित लागत 360.00 लाख 2. घुनघुनिया जैन मंदिर से जगदीश मंदिर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सौंदर्यकरण मार्ग का निर्माण कार्य लं. 1.10 कि.मी. का निर्माण कार्य अनुमानित लागत 288.87 लाख

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	रिमार्क
2025_PWDRB_ 407456_1	सागर	6488700	648870	20000	08 माह वर्षाकाल सहित	द्वितीय आमंत्रण

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. लोक निर्माण विभाग उपसंभाग रहली के अंतर्गत विभिन्न मार्गों का निर्माण कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित लं. 7.60 कि.मी. अनु. लागत 746.52 लाख 1. खेजरा धनगुवा तिखि भैसा मार्ग का निर्माण कार्य लं. 5.80 कि.मी. अनुमानित लागत 545.04 लाख 2. चांदपुर से घाटा देवी मंदिर मार्ग का निर्माण कार्य लं. 1.80 कि.मी. का निर्माण कार्य अनुमानित लागत 201.48 लाख

2025_PWDRB_ 407457_1	सागर	74652000	746520	20000	08 माह वर्षाकाल सहित	द्वितीय आमंत्रण
		139539000				

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 8.03.2025 समय 10.00 बजे से दिनांक 24.03.2025 समय 17.30 तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता
जी-24253/50667/2025 **लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र सागर**

कार्यालय मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र सागर

फोन नं. : 07582-220840, ईमेल आईडी : cepwdsagar@nic.in

एनआईटी नं. - 15/2024-25/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण **सागर, दिनांक : 06.03.2025**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :–

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्र.1 सागर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों का निर्माण कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित लं. 4.90 कि.मी. अनु. लागत 533.93 लाख 1. केवलारी से सहजपुरी बुजुर्ग मार्ग का निर्माण कार्य लं. 2.50 कि.मी. अनुमानित लागत 257.57 लाख 2. सहजपुरी बुजुर्ग से सहजपुरी खुर्द मार्ग लं. 2.40 कि.मी. का निर्माण कार्य अनुमानित लागत 276.36 लाख

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	रिमार्क
2025_PWDRB_ 407288_1	सागर	533.93	533930	20000	08 माह वर्षाकाल सहित	द्वितीय आमंत्रण

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. ग्राम बिलहरा बेरखेड़ी निर्टर्ी मार्ग का निर्माण कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित अनुमानित लागत 748.88 लाख।

2025_PWDRB_ 407295_1	सागर	748.88	748880	20000	08 माह वर्षाकाल सहित	द्वितीय आमंत्रण

क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. ग्राम झिला से मुरलीबासौदा मार्ग का निर्माण कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित अनुमानित लागत 612.07 लाख।

2025_PWDRB_ 407299_1	सागर	612.07	612070	20000	08 माह वर्षाकाल सहित	द्वितीय आमंत्रण
	योग	**1894.88**				

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 7.03.2025 समय 10.00 बजे से दिनांक 21.03.2025 समय 17.30 तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता
जी-24163/50663/2025 **लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र सागर**

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ce.tender.wrdmp@gmail.com, फोन - 0755-276735, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 1134/2024-25/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक : 11.03.2025**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र दिनांक 01.04.2025 को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2025_ WRD_ 406706	गोठडा से शनि मंदिर तक कान्ह नदी के दोनों तटों पर घाट निर्माण एवं शिप्रा नदी के बायें एवं दाएं तट पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक घाट निर्माण कार्य एवं आत्मलिंगेश्वर मंदिर के पास, भर्तहरी की गुफा के पास, अंगारेश्वर मंदिर के पास वेटेड कॉजवे का निर्माण कार्य एवं कान्ह नदी पर पंथपिपलाई, जमालपुरा, गोठड़ा, स्टॉप डेम, पिपलिया राघो बैराज नं. 2, रामवासा बैराज नं. 02 का स्टॉप डेम का निर्माण कार्य एवं शिप्रा नदी पर किथोदाराव बैराज का निर्माण कार्य एवं उन्डासा और जस्तावेड़ी तालाब का मरम्मत कार्य एवं दुर्गादास की छतरी के पास सीसी रोड का निर्माण कार्य।	उज्जैन	59362.28

जी-24241/50664/2025 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, निर्माण संभाग क्रमांक-1 राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

क्रमांक-677/व.ले.लि. **भोपाल, दिनांक : 12.03.2025**

निविदा निरस्तीकरण सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना क्रमांक 50/व.ले.लि. **दिनांक 28.02.2025** को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

कार्यपालन यंत्री
निर्माण संभाग क्रमांक-1
जी-24251/50666/2025 **राज.परि. प्रशासन, लो.नि.वि. भोपाल ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल**

अनुपूरक बजट में एमएसएमई के लिए 1075 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान

भोपाल, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने राज्य विधानसभा में 19,206 करोड़ 79 लाख 52 रुपये का वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया है। इसमें एमएसएमई विभाग के लिए 1075 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप ने इस बजट प्रावधान के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के प्रयासों से प्रदेश में निवेश और औद्योगिकीकरण को नई गति एवं दिशा प्राप्त होगी। प्रदेश में रोज़गार की नई संभावना में वृद्धि होगी और संपूर्ण प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

अनुपूरक अनुमान में यह राशि एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रदाय योजना के तहत पिछले वर्षों के बकाया भुगतान के लिए प्रस्तावित है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट में 694 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। प्रथम अनुपूरक अनुमान में 400 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसका वितरण सिंगल क्लिक से संबंधित इकाइयों को किया जा चुका है। द्वितीय अनुपूरक अनुमान और पूर्व में आवंटित राशि को मिलाकर विभाग के लिये इस वित्तीय वर्ष में 2169.80 करोड़ रुपये का कुल बजट प्रावधान हो जायेगा। निवेश प्रोत्साहन के दृष्टिगत विभाग के लिये पहली बार इतने बजट का प्रावधान किया गया है।

समग्र विकास पर काम कर रही है सरकार खेल और खिलाड़ी हमारी प्राथमिकता

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जहांनुमा पैलेस में एक निजी मीडिया समूह द्वारा आयोजित 'पंख खेल उपलब्धि पुरस्कार-2025' कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समग्र विकास के रोडमैप पर हमारी सरकार काम कर रही है। खेलों का विकास हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। खेल और खिलाड़ी दोनों हमारी प्राथमिकता में हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं के लिए समर्पित दिन है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाएं, जिन्होंने राज्य को गौरवान्वित किया है, उन्हें सम्मानित करना सरकार के लिए हर्ष का विषय है।

मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण जन्म के वृत्तांत का वर्णन कर बताया कि सामाजिक सरोकार के महत्व को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। अपने विराट व्यक्तित्व से उन्होंने सामाजिक चेतना जागृत की। उन्होंने कहा कि समाज के व्यक्तियों द्वारा राज्य के उभरते खिलाड़ियों की मदद कर उन्हें खेल में सहयोग करना, हमारी सामाजिक जीवंतता का सहज प्रमाण है। इस प्रकार के विशेष आयोजन के लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जनहित से जुड़े विभिन्न प्रभावकारी निर्णयों, कोविड के समय वैक्सीन का त्वरित उत्पादन, कोविड महामारी रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा करना, नोटबंदी की घोषणा करना, सर्जिकल स्ट्राइक आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सभी राष्ट्रहित के निर्णय हैं। हम सभी के लिए यह निर्णय प्रेरणादायी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सदैव राजधर्म का पालन करना पड़ता है। इसलिए कभी-कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं।

विगत एक वर्ष में हमने जनहित में कई बड़े निर्णय लिए हैं। हम प्रदेश के विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हरसंभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में देश का विकास जनता की भागीदारी से ही संभव है। लोकतंत्र में करोड़ों लोग देश के विकास में सहभागिता करते हैं।

मतदान करने वाला हर व्यक्ति देश के विकास का सहभागी है। हमारा प्रत्येक निर्णय जनभावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि हम सभी सामाजिक प्रेरणा से देश का विकास करने और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहें। यही राष्ट्रधर्म है, यही नागरिक धर्म है।

मां नर्मदा के परिक्रमा पथ को मूल स्वरूप में स्थापित करने के लिए हैं दृढ़ संकल्पित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ओंकारेश्वर में आयोजित 'अमृतस्य मां नर्मदा पद परिक्रमा' कार्यक्रम को संबोधित किया

खंडवा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ओंकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट पर आयोजित अमृतस्य मां नर्मदा पद परिक्रमा कार्यक्रम में शामिल हुए और मां नर्मदा की पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ओंकारेश्वर में भव्य ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाया जाएगा। मार्च माह के बाद चिह्नित तीर्थ स्थलों पर शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन के लिए जल महत्वपूर्ण है। जैसे जल संरचना नदी-तालाब के दर्शन मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है। मानव शरीर में जिस प्रकार धमनियों में रक्त का प्रवाह होता है उसी प्रकार धरती पर नदियां बहती हैं इसलिए उन्हें पवित्र रखना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मां नर्मदा के संपूर्ण परिक्रमा पथ को पवित्रता के साथ उसके मूल स्वरूप में स्थापित करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में जहां भी नर्मदा तट हैं वहां आयोजनों के लिए घाटों का निर्माण किया जाएगा एवं यात्रियों की सुविधा के लिए साइनऐप लगाये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश नदियों का मायका है, जिसमें मां नर्मदा का स्थान सभी नदियों में सबसे अलग है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार स्वच्छता के माध्यम से विकास के कार्य को भी नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है।

- **प्रदेश में नर्मदा के संपूर्ण तट पर धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाएगा घाटों का निर्माण।**
- **मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में मां नर्मदा की पूजा-अर्चना की।**
- **मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन कर किया जलाभिषेक।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैमिकल युक्त खेती करने से फसल का उत्पादन तो होता है, लेकिन जीवन में अनेक बीमारियां भी होती हैं, इससे बचने के लिए एक अभियान संचालित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक तथा जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गौ-माता का पालन करना होगा, जिससे दूध उत्पादन के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय त्योहार भी शासकीय तौर पर मनाये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समृद्धि, विकास और कल्याण की प्रार्थना की।

इंदौर को सिग्नल-लैस बनाने की योजना

इंदौर, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, इंदौर को सिग्नल-लैस शहर बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य शहर में यातायात को निर्बाध रूप से संचालित करना है। योजना के तहत फ्लाई-ओवर, बाय-लेन, अंडर पास और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहल लागू की जा रही हैं। योजना के पूरा होने पर इंदौर शहर में नागरिकों का यात्रा समय कम होगा और ट्रैफिक सुचारु रहेगा। सिग्नल-लैस योजना तेजी से बढ़ते शहरी यातायात को सुविधाजनक बनाने और यात्रा समय को कम करने में मदद करेगी। ऑटोफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग यातायात प्रबंधन को अधिक स्मार्ट और कुशल बनाने में भी किया जा रहा है।

ग्रीष्मकालीन मूंग में कीटनाशक का उपयोग कम करें

भोपाल, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि किसान ग्रीष्मकालीन मूंग में कीटनाशक एवं खरपतवारनाशक दवाइयों का उपयोग कम करें। प्रदेश में लगभग 14.39 लाख हेक्टेयर में तीसरी फसल के रूप में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल ली जा रही है, जिसका उत्पादन 20.29 लाख मीट्रिक टन एवं औसत उत्पादकता 1410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती मुख्यत: नर्मदापुरम, जबलपुर एवं भोपाल संभाग में की जाती है। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में कीटनाशक एवं खरपतवारनाशक दवा का उपयोग कम से कम करें।

समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन रहे सामूहिक विवाह

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केसला, नर्मदापुरम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब गरीब परिवार बेटी का विवाह कर कर्ज में डूब जाते थे। बेटी के जन्म के साथ ही उसकी शादी की चिंता सताती थी। लेकिन, अब सरकार बेटियों का कन्यादान कर रही है। माता-पिता अब बेटियों के जन्म पर उदास नहीं होते बल्कि, बधाई गीत गाते हैं। निर्धन परिवार की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना वरदान सिद्ध हुई है। सामूहिक विवाह में 508 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। यहां एक कल्याणी और एक दिव्यांग बहन का भी विवाह सम्पन्न हुआ।

- **सामूहिक विवाह में 508 जोड़ों का हुआ विवाह।**
- **एक कल्याणी और एक दिव्यांग बहन भी परिणय सूत्र में बंधी।**
- **लाड़ली बहना योजना और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं।**

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परिणय सूत्र में बंधे नव दम्पतियों को बधाई व शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में से पाणिग्रहण अर्थात विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। सामूहिक विवाह में सम्मिलित प्रत्येक नव विवाहित जोड़े को मंगल आशीष के रूप में 49 हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। सामूहिक विवाह समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन रहे हैं। यह मितव्ययता और सामाजिक समरसता का संदेश भी देते हैं। भारतीय परम्परा में विवाह कोई समझौता या एग्रीमेंट नहीं, अपितु जन्म-जन्मांतर तक चलने वाला पवित्र बंधन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में नारी सशक्तिकरण मिशन आरंभ किया गया है। लाड़ली बहना योजना और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं।

निवेश बढ़ाने के लिये औद्योगिक इकाइयों को हर संभव मदद दी जायेगी

इंदौर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने धार जिले के पीथमपुर में मान ग्रुप की मान इंडस्ट्री का उद्घाटन किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकार ने हर कदम पर औद्योगिक कम्पनियों को उद्योग लगाने और निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिये उद्योग संवर्धन नीति में बदलाव किये हैं। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मान कम्पनी की नई यूनिट के उद्घाटन से युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में लगातार औद्योगिक विकास हो रहा है।

मान ग्रुप के चेयरमैन डॉ. रमेश मनसुखानी ने बताया कि हमारी कंपनी गुजरात, जम्मू, अबूधाबी एवं सउदी अरब में उद्योग स्थापित करने के बाद अब पीथमपुर में अपना नया प्लांट स्थापित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि मान इंडस्ट्री ग्रुप अत्यंत गर्व और विनम्रता के साथ मध्यप्रदेश की भूमि से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमने पहला निर्माण संयंत्र पीथमपुर में स्थापित किया था। पिछले तीन दशकों में हमें प्रदेश के औद्योगिक विकास और देश के ऊर्जा सेक्टर में योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारा संगठन 25 देशों के वैश्विक ग्राहकों को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

जनजातीय संस्कृति में भगोरिया हाट का है विशेष महत्व - मुख्यमंत्री

बड़वानी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़वानी जिले के पानसेमल के पारंपरिक लोक उत्सव भगोरिया हाट में कहा कि जनजातीय संस्कृति में भगोरिया का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि हमारे त्योहार और संस्कृति हमारी परम्परा को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने जनजातीय वेशभूषा पहनकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विशेष रूप से सजी हुई गाड़ी में भगोरिया मेले का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने सभी को भगोरिया उत्सव एवं होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगोरिया में पानसेमल क्षेत्र की जनजातीय संस्कृति देखने को मिली।

यह पर्व रबी की फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। इसमें ग्रामीण भाई-बहन त्योहारों के लिए विशेष खरीदी करते हैं। त्योहारों में हम एक दूसरे से आपस में मिलकर आपसी वैमनस्य को समाप्त कर भाईचारा बनाये रखते हैं। हम सब एक दूसरे से मिल-जुलकर हमेशा जुड़े रहें यही हमारे त्योहारों की विशेषताएं हैं, इसलिए हमें अपने त्योहार, अपनी संस्कृति एवं परंपराओं का सम्मान करते हुए इन्हें सहेजना चाहिए।

मुख्यमंत्री का हुआ भव्य स्वागत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पानसेमल नगरवासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। नगरवासियों ने अपनी दुकान, घरों, छतों, चौराहे से पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्वागत किया।

ढोल-मांदल बजाने वाले समूहों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उनके स्वागत में आये स्थानीय ढोल-मांदल बजाने वाले समूहों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ढोल-मांदल की थाप पर स्वत: पैर थिरकने लगते हैं। संस्कृति संरक्षण के लिये कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रत्येक समूह को 5-5 हजार रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

मध्यप्रदेश जैव-विविधता संरक्षण के साथ वन्य जीवों के सह-अस्तित्व का उदाहरण

भोपाल, मध्यप्रदेश ने वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को प्रदेश का 9वां टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 58वें और मध्यप्रदेश के नौवें टाइगर रिज़र्व की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा, 'भारत वन्य जीव विविधता से समृद्ध है, यहां की संस्कृति वन्य जीवों का सम्मान करती है। हम हमेशा पशुओं की रक्षा करने में सबसे आगे रहेंगे।' उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मध्यप्रदेश के 9वें टाइगर रिज़र्व के शुभारंभ के प्रतीक स्वरूप एक बाघिन को स्वच्छंद विचरण के लिए मुक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नए बाघ अभयारण्य को विकसित करते समय अन्य प्रजातियों के सह-अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह कोई चिड़ियाघर नहीं है, बल्कि एक खुला आवास है, जो वन्य जीवों और आम जनता दोनों के लिए सुलभ है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में मानव और वन्य जीवों के सह-अस्तित्व का अनोखा परिदृश्य मौजूद है। इस कदम से बाघों के संरक्षण को नया बल मिलेगा और जैव विविधता को सहेजने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के 9 टाइगर रिज़र्व मध्यप्रदेश के प्राकृतिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

'भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2023' के अनुसार, मध्यप्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। राज्य का वन आवरण क्षेत्र 77,073 वर्ग किलोमीटर है, जो देश में सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश ने देश में सबसे पहले 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था।

मध्यप्रदेश में सबसे अधिक 9 टाइगर रिज़र्व हो गए हैं। इनमें कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, वीरांगना दुर्गावती, संजय-डुबरी, रातापानी और अब माधव टाइगर रिज़र्व शामिल हैं। प्रदेश में 11 नेशनल पार्क, 24 अभयारण्य हैं। सफेद बाघों के संरक्षण के लिए मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी विकसित की गई है।

कभी सिंधिया रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहे शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा वर्ष 1958 में की गई थी। अब यह टाइगर रिज़र्व बन गया है। इसका क्षेत्रफल 375233 वर्ग किलोमीटर है।

जल की बूंद-बूंद बचायें, जल से ही सुरक्षित होगा हमारा कल - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में हुई 'जल गंगा जल संवर्धन अभियान' की बैठक

- **30 मार्च को गुड़ी पड़वा से होगा 90 दिवसीय जल गंगा जल संवर्धन अभियान का शुभारंभ।**
- **उज्जैन में क्षिप्रा तट से होगी प्रदेशव्यापी जल संरक्षण अभियान की शुरुआत।**
- **30 मार्च से 30 जून तक चलेगा अभियान।**
- **अभियान में होगा 50 हजार नए खेत-तालाबों का निर्माण।**

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में हुई 'जल गंगा जल संवर्धन अभियान' की बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी से ही जिंदगानी है। हम सभी को जल की बूंद-बूंद बचाने की जरूरत है। जल से ही हम सबका आने वाला कल सुरक्षित है। जल गंगा जल संवर्धन अभियान में जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक गतिविधियां चलाई जाएं। जन सामान्य में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार विभिन्न विभागों, सामाजिक संगठनों और आम जनता की भागीदारी से जल संरक्षण गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। अभियान में वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दिया जाए। जल गंगा संवर्धन अभियान गुड़ी पड़वा 30 मार्च से प्रारंभ होकर 30 जून, 2025 तक तीन माह लगातार चलेगा।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अभियान की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देकर अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ें। उन्होंने कहा कि जल गंगा जल संवर्धन अभियान से प्रदेश में जल संकट को कम करने में मदद मिलेगी और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के अंतर्गत जल संचय की विभिन्न गतिविधियां चलाई जाएं। उन्होंने कहा कि पौधरोपण एवं जल स्रोतों का पुनर्जीवन, गांव-गांव में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यों के अलावा सामुदायिक सहभागिता के जरिए जल संरक्षण के प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि स्कूलों में बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए सकारात्मक अभियान की शुरुआत की जाए।

राज्य स्तरीय जल गंगा जल संवर्धन अभियान का शुभारंभ आगामी 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के दिन से उज्जैन की क्षिप्रा नदी के तट से किया जाएगा। लगभग 90 दिन चलने वाले 'जल गंगा जल संवर्धन अभियान' का समापन 30 जून 2025 को होगा।

बैठक में बताया गया कि गत वर्ष 5 जून से 30 जून 2024 तक जल गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया गया था। इस अवधि में 1056 करोड़ रुपये की लागत से 38 हजार 851 नवीन कार्य किए गए।

अब किसान वर्ष में तीन बार फसलें पैदा करेंगे

मंदसौर, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर जिले के ग्राम रठाना और भावता में 26 करोड़ 63 लाख 76 हजार की लागत से निर्मित होने वाली 6 सड़कों का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से अब किसान एक वर्ष में 3 बार फसल पैदा कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि, 2047 में देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत होगी। 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता की ताकत को आधार बनाकर देश को विश्वगुरु के स्थान पर लाने का संकल्प सरकार ने लिया है। आर्थिक रूप से देश संपन्न होगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि मंदसौर में औद्योगिक निवेश हो इस पर लगातार कोशिश की जा रही है। कोई भी परिवार बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, गरीब, किसान, महिलाओं के उत्थान के लिये काम कर रही है।

प्रदेश को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में बजट निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका

भोपाल, पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रदेश को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। प्रदेश को एक समृद्ध और आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की यह ऐतिहासिक कदम है। राज्यमंत्री श्री लोधी ने कहा कि बजट में पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक प्रावधान किए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश को पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व के लिए कुल 1,610 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 133 करोड़ रुपये अधिक है।

उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर में 'ओंकारेश्वर महालोक' का निर्माण किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को आधुनिक और भव्य सुविधाएं मिलेंगी।

आचार्य शंकर अद्वैत वेदान्त संस्थान-अद्वैत वेदान्त के प्रणेता आचार्य शंकर के विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान की स्थापना की जा रही है। वेदान्त पीठ की स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश को फ्लाई ऐश के कुशल प्रबंधन के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

भोपाल, मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी (एमपीपीजीसीएल) के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी व अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई को फ्लाई ऐश के कुशल व प्रभावी प्रबंधन करने के लिए फ्लाई ऐश उपयोगिता-2025 विषय पर गोवा में आयोजित 14 वें अन्तर्राष्ट्रीय आवासीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया। तीनों विद्युत गृह के अभियंताओं को यह पुरस्कार पूर्व केन्द्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदान किया।

सहकारिता विभाग के सभी 25 अनुकंपा नियुक्ति आदेशों का वितरण

भोपाल, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सहकारिता का संकल्प नए आयाम स्थापित करेगा। सहकारिता के माध्यम से ही समृद्धि स्थापित होगी। जरूरत है मेहनत, लगन और पारदर्शिता की। श्री सारंग ने कहा कि नवाचार से किये गये कार्य के जरिये व्यक्ति नई ऊंचाईयों को पा सकता है। श्री सारंग ने अपेक्स बैंक परिसर स्थित समन्वय भवन में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजनांतर्गत ई-पैक्स प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता विभाग में 25 अनुकम्पा नियुक्ति पाने वालों को नियुक्ति आदेश भी प्रदान किये।

श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता में ब्रांडिंग और दृढ़ता के साथ काम करने की भावना स्थापित हो। नित नये नवाचार के जरिये अपनी पहचान बनाएं। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में उदाहरण है जिन्होंने काम किया लोग उन्हें ही याद रखते हैं। इसलिये स्वयं अपने व्यक्तित्व निर्माण के साथ उत्कृष्ट कार्य करें, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलें और लोग उन्हें याद रखें।

श्री सारंग ने कहा की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने की चाहत सफल बनाती है। सहकारिता के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था का उन्नयन किया जा सकता है।

प्रदेश के 700 हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रारंभ होगी व्यावसायिक शिक्षा

भोपाल, प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जा रही नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रत्येक बिंदु को ठोस तरीके से लागू किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में तेजी से बढ़ती हुई विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का किस प्रकार से योगदान हो उसकी चिंता की गई है। बढ़ती हुए आबादी के साथ जनता के लिये उनकी शिक्षा, कौशल और आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार का सृजन एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दे रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने नये शैक्षणिक सत्र में 700 नये उच्चतर माध्यमिक

विद्यालयों में नये ट्रेड एवं जॉब रोल्स शुरू करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के शिक्षा विभाग को भेजा है। यह ट्रेड 21वीं सदी के नवीन कौशल उन्नयन पर आधारित है।

वर्तमान में 2383 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स चल रहे हैं। प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या 3 हजार से अधिक हो जायेगी।

वर्तमान में संचालित कोर्स में कक्षा 9 और 10 में डाटाएंट्री ऑपरेटर, जूनियर फील्ड टेकनीशियन, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, रिटेल स्टोर, ऑपरेशन असिस्टेंट, प्रावेट सिक्योरिटी गॉर्ड, फूड एण्ड बेवरीज, सर्विस असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट आदि विषय प्रमुख है, कक्षा 11 और 12 में जिन कोर्स को प्राथमिकता दी गई है।

प्रदेश में वर्तमान में 2383 विद्यालयों में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा देने के लिये 4 हजार 700 से अधिक शिक्षकों को विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 जारी

मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर 15,03,395 करोड़ रुपये पहुंचा

भोपाल, मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 प्रचलित भावों पर रुपये 15,03,395 करोड़ पहुंच गया है, जो वर्ष 2023-24 में रुपये 13,53,809 करोड़ था। पिछले वित्तीय वर्ष से 11.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ने वर्ष 2028-29 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

विधानसभा में प्रस्तुत मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 में स्थिर भावों पर जीएसडीपी 7,12,260 करोड़ रुपये है जो वर्ष 2023-24 में 6,71,636 करोड़ रहा। यह 6.05 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दिखाता है। मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 प्रचलित भावों पर रुपये 1,52,615 हो गई है। स्थिर भाव पर वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय रुपये 70,434 है।

मध्यप्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में प्रचलित भावों पर वर्ष 2024-25 में क्षेत्रवार हिस्सेदारी क्रमशः प्राथमिक क्षेत्र में 44.36 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 19.03 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र में 36.61 प्रतिशत रही है।

मध्यप्रदेश ने लोक वित्त में अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रभावी कदम उठाये हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व अधिशेष रुपये 1,700 करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 4.11 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। राजस्व प्राप्तियां रुपये 2,63,344 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि फसल क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत योगदान वर्ष 2024-25 में 30.90 प्रतिशत रहा लेकिन प्रचलित भाव पर यह 10.8 प्रतिशत बढ़ा जबकि स्थिर भाव में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई इसी तरह पशुधन क्षेत्र में 7.45 प्रतिशत का योगदान रहा। इसकी वृद्धि स्थिर भाव पर क्रमशः 11.93 प्रतिशत एवं 8.39 प्रतिशत रही।

'विकसित भारत' की कल्पना के अनुरूप विकसित मध्यप्रदेश के रूप में राज्य अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगा। प्रदेश की मजबूत बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय समावेश की शक्ति से आर्थिक तंत्र निरंतर सशक्त हो रहा है।

कृषि और कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से आय के स्रोतों में वृद्धि हो रही है, जबकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, बड़ी अधोसंरचनात्मक परियोजनाएं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विस्तार और ऊर्जा उपलब्धता में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण घटक एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में प्रदेश की प्रगति को दर्शाते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, और नारी शक्ति जैसे चार प्रमुख मिशनों की शुरुआत की है। ये मिशन क्रमशः समाज के वंचित वर्गों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के समग्र विकास एवं आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देने के लिए मानकों के सरलीकरण,

जनविश्वास बिल, राजस्व महाभियान और पीएम जनमन कार्यक्रम जैसे प्रभावी उपायों को अपनाया है, जिससे सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 प्रदेश की आर्थिक प्रतिबद्धताओं, विकास योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह सर्वेक्षण राज्य की विकास यात्रा को प्रतिबिंबित करता है और यह दर्शाता है कि मध्यप्रदेश सतत और समावेशी आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 को 'उद्योग वर्ष' घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्वितीयक क्षेत्र में 2.73 लाख करोड़ रुपये के सकल मूल्य वर्धन तक पहुंच गया। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिये वर्ष 2024-25 में 145.13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई तथा दिसम्बर 2024 तक 4.17 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

राज्य में सामाजिक क्षेत्र के लिये महत्वपूर्ण बजटीय आवंटन किये गये हैं जिसमें पिछले चार वर्षों में 82.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने समस्त बाल विकास को प्राथमिकता देते हुये राज्य के कुल बजट का 21.6 प्रतिशत बजट आवंटित किया है। 'पोषण भी पढ़ाई भी', 'स्व-सहायता समूह', 'सामुदायिक संस्थागत विकास', 'लखपति दीदी', 'विकसित मध्यप्रदेश विजन 2047' आदि इस दिशा में अग्रणी प्रयास है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य का बजट वर्ष 2024-25 में 15,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4.85 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किये गये हैं।

वर्ष 2024-25 में शिक्षा का बजट 11.26 प्रतिशत आवंटित किया गया है। सी.एम. राइज़ स्कूल योजना के तहत 274 स्कूलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। व्यावसायिक शिक्षा में 14 ट्रेड्स शुरू किये गए हैं। उच्च शिक्षा के अंतर्गत 1346 महाविद्यालय में 10.5 लाख सीट उपलब्ध है। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 3.49 लाख छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है।

राज्य अधिसूचित वन क्षेत्र 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर तथा वनावरण 77.07 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ अग्रणी स्थिति पर है। वर्ष 2024 में राज्य का भू-जल संसाधन 35.90 बीसीएम पहुंच गया है। राज्य में वर्ष 2023-24 में खनिज उत्पादन मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 16.71 प्रतिशत अधिक रहा है। माइनिंग कान्क्लेव 2024 में रुपये 19250 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को रुपये 472.28 करोड़ का बजट आवंटित किया है। राज्य में 10 आई.टी. पार्क एवं 4 आई.टी. SEZ विकसित किये गये हैं। राज्य में 4895 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप कार्यरत हैं।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

फैक्ट फाइल

वर्तमान परिदृश्य और पर्यावरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिक वाहन को किया जा रहा है प्रोत्साहित

निवेशकों को मिले प्रोत्साहन से प्रदेश का ऑटोमोबाइल सेक्टर पकड़ेगा रफ्तार

वर्तमान परिदृश्य और पर्यावरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में विशेष प्रयासों के चलते इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण के साथ नवाचार और अनुसंधान भी किये गये। निवेशकों को दी जाने वाली सुविधाओं के परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है जो प्रदेश में ईवी क्रांति के साथ निवेश की संभावनाओं को भी रेखांकित करती है। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटोमोबाइल सेक्टर को गति मिली है। ईवी के क्षेत्र में होने वाले विस्तार से प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। आर्थिक समृद्धि के साथ हम हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर होंगे।

प्रदेश में प्रमुख ईवी और ऑटोमोबाइल इकाई

प्रदेश में 30 से अधिक मूल उपकरण निर्माता कंपनियां कार्यरत हैं और 200 से अधिक कंपनियां वाहन कल-पुर्जों का निर्माण कर रही हैं। जीआईएस- भोपाल में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान इलेक्ट्रो-ग्रेफाइड (एचईजी) ने 1800 करोड़ रुपये के निवेश का करार किया। देवास में बनने वाले इस संयंत्र में ग्रेफाइड एनोड का उत्पादन होगा, जिससे ईवी बैटरियों की लागत में कमी आएगी और उद्योग को नया प्रोत्साहन मिलेगा।

पीथमपुर में क्या विशेष

मध्यप्रदेश का पीथमपुर ऑटो-क्लस्टर लगभग 4,500 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल केंद्रों में से एक बन चुका है। यहां फोर्स मोटर्स, आयशर मोटर्स, एसीटीएसी मोटर्स, काइनेटिक मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियां कार्यरत हैं। साथ ही, 60 से अधिक ऑटो कल-पुर्जा निर्माता कंपनियां यहां अपने उत्पाद बना रही हैं। पीथमपुर में स्थित एशिया का सबसे लंबा हाई-स्पीड टेस्टिंग ट्रैक 'नैट्रैक्स' (11 किलोमीटर) वाहन परीक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जो इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है।

- प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटोमोबाइल सेक्टर के बढ़ते कदम।
- जीआईएस भोपाल में देश दुनिया की प्रमुख ऑटोमोबाइल और ईवी कंपनियां हुईं शामिल।
- स्वच्छ और सस्टेनेबल ऑटोमोबाइल निर्माण को बढ़ाने के लिए सरकार ने लागू की विशेष नीतियां।
- चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रोजन फ्यूल इनोवेशन में बढ़ता निवेश।
- मध्यप्रदेश वाणिज्यिक वाहन निर्माण में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल।
- बस और ट्रेक्टर निर्माण में दूसरे स्थान पर।
- मध्यप्रदेश में ईवी बैटरी निर्माण

जीआईएस में एमपी मोबिलिटी एक्सपो

जीआईएस समिट में एमपी मोबिलिटी एक्सपो-2025 का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिजस्टोन, ज़ेडएफ स्टीयरिंग, मदरसन गेबियल, आनंद इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों ने भाग लिया। एक्सपो में सुपर कार और सुपर बाइक प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। विभिन्न स्टार्ट-अप्स ने नवाचार प्रस्तुत किए, जिससे प्रदेश में नई तकनीकों के समावेश को बढ़ावा मिला।

निवेशकों को सुविधाएं और बढ़ता निवेश

मध्यप्रदेश सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कर-प्रोत्साहन, शीघ्र अनुमोदन प्रक्रिया और उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा दे रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश के ऑटोमोबाइल और वाहन कल-पुर्जा क्षेत्र ने 19.2 करोड़ डॉलर मूल्य का निर्यात किया।

जीआईएस में शामिल प्रमुख कंपनियां

जीआईएस-भोपाल में ऑटो मोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की प्रमुख कंपनियों ने हिस्सेदारी की। ऑटो एक्सपो में ब्रिजस्टोन, जेडएफ स्टीयरिंग, बाडवे इंजीनियरिंग, मदरसन गेबियल, पिस्टल देवास, आनंद इंडस्ट्रीज, झालानी इंजीनियर्स, एसडी एक्सेल प्रा. लिमिटेड, जगतजीत इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, टैफे मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड, वी.ई. कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड और पिनेकल इंडस्ट्रीज शामिल थीं।

इस क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि ऑटो-मोबिलिटी के विस्तार से मध्यप्रदेश में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन नीति को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे राज्य न केवल आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होगा, बल्कि हरित ऊर्जा और सतत् विकास की दिशा में भी मिसाल कायम करेगा।

- शशांक मणि पांडे

(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

चर्चा में

भारत सरकार ने

भारतीय रेलवे वित्त निगम को नवरत्न का दर्जा दिया

केन्द्र सरकार ने रेल मंत्रालय के अधीन मात्र 41 कर्मचारी वाले पीएसयू भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया। मंत्रालय ने कहा कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना आईआरएफसी की वित्तीय ताकत और भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे को मदद करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आईआरएफसी रेलवे के अलावा अब उन क्षेत्रों में भी निवेश के अवसर तलाश रहा है, जो रेलवे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जैसे कि बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, खनन, ईंधन, कोयला, वेयरहाउसिंग, टेलीकॉम, होटल एवं कैटरिंग। कंपनी ने एनटीपीसी के लिए 20 BOBR रेक्स की 700 करोड़ रुपये की फंडिंग का समझौता किया है। आईआरएफसी भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स, रेलवे की नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकताओं, मेट्रो रेल परियोजनाओं, बंदरगाह रेल कनेक्टिविटी और पीपीपी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

मार्क कार्नी

कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे

बैंकर मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे। कार्नी को लिबरल पार्टी का नेता चुन लिया गया है। 59 वर्षीय कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। कार्नी ने लिबरल पार्टी का नेता चुनने के लिए हुई वोटिंग में 85.9 फीसदी वोटों से शानदार जीत हासिल की है। लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने के लिए मार्क के सामने पूर्व उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी उम्मीदवार थीं, जिन्हें केवल आठ प्रतिशत वोट मिले। कार्नी ऐसे समय में कनाडा के प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं, जब देश अमेरिका से तनातनी का सामना कर रहा है। कार्नी ने अपनी जीत के बाद अमेरिका की व्यापार नीतियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा की संप्रभुता की रक्षा करने की बात कही है।

अंजू राठी राणा

केंद्रीय विधि सचिव बनने वाली पहली महिला बनीं

भारतीय विधि सेवा की अधिकारी अंजू विधि सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। पिछले सप्ताह उनकी नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। वर्ष 2017 में उन्हें विधि मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। वह 18 वर्ष तक दिल्ली सरकार में सरकारी वकील भी रही थीं। आईएएस अधिकारी नितेन चंद्र कुछ महीने पहले तक विधि सचिव थे और तब से यह पद रिक्त था। वह राजीव मणि का स्थान लेंगी, जो वर्तमान में इस पद का अंतरिम प्रभार संभाल रहे थे। डॉ. राणा ने ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कानूनी सुधारों और न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित किया है।

अजय भादू

जीईएम के सीईओ नियुक्त

सरकार ने वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव अजय भादू को सार्वजनिक खरीद मंच जीईएम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि वह विभाग में अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के अलावा यह भूमिका भी संभालेंगे। सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल नौ अगस्त, 2016 को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए शुरू किया गया था। भादू गुजरात कैडर के वर्ष 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।

प्लास्टिक-आइस-7

वैज्ञानिकों ने खोज लिया पानी का चौथा स्वरूप

पानी के रहस्यों से पर्दा हटाते हुए वैज्ञानिकों ने इसका एक नया और दुर्लभ स्वरूप खोजा है, इसे प्लास्टिक आइस-7 नाम दिया गया है। जल के तीन रूप ठोस, द्रव और गैस से आगे यह बर्फ का एक अनोखा चरण है, जो अत्यधिक दबाव और उच्च तापमान में बनता है। फ्रांस की सॉरबोन यूनिवर्सिटी की लिविया बोवे के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने पहली बार इसके अस्तित्व की पुष्टि की है। अत्याधुनिक विधियों से उन्होंने उच्च दबाव में पानी के अणुओं की गति को परमाणु स्तर पर देखा और उसका विश्लेषण किया।

नासा ने

पहली बार चांद पर इस्तेमाल किया GPS

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार चंद्रमा पर GPS सिग्नल को सफलतापूर्वक ट्रैक किया। यह उपलब्धि लूनर GNSS रिसीवर एक्सपेरीमेंट (LuGRE) की मदद से हासिल हुई, जिसे 3 मार्च को चंद्रमा पर सिग्नल प्राप्त करने में सफलता मिली। यह तकनीक पृथ्वी के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) का उपयोग करती है, जिससे चंद्रमा पर भी नेविगेशन संभव हो सकेगा। इस मिशन में नासा के साथ इटली की अंतरिक्ष एजेंसी भी शामिल रही।

एनवीडिया ने

आनुवंशिक अनुसंधान के लिए एआई प्रणाली की तैयार

एआई चिप निर्माता एनवीडिया और अनुसंधान साझेदारों ने जैविक अनुसंधान के लिए अब तक की सबसे बड़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली बनाई है। प्रारंभिक परीक्षणों में इसने स्तन कैंसर से जुड़े जीन BRCA1 में संभावित हानिकारक उत्परिवर्तनों में से 90 प्रतिशत की सटीक पहचान की। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे अधिक सटीक उपचार विकसित करने में मदद मिल सकती है, जिसमें केवल विशिष्ट कोशिकाओं को लक्षित करने वाली जीन थेरेपी भी शामिल है। यह मॉडल अमेजन के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2,000 एनवीडिया एच 100 प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया गया था। आर्क इंस्टीट्यूट और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर विकसित किया गया इवो 2 अब एनवीडिया के बायोनेमो अनुसंधान प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।

सी-डॉट ने

केरल पुलिस के लिए बनाया 'त्रिनेत्र'

दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने केरल पुलिस के लिए साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र 'त्रिनेत्र' डिजाइन और विकसित किया है। केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने पुलिस प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस केंद्र 'त्रिनेत्र' का उद्घाटन किया। सी-डॉट का 'त्रिनेत्र' समाधान एक एआई-संचालित, स्वदेशी, एकीकृत साइबर सुरक्षा मंच है जिसे उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है।

यामंडु ओर्सी

उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने

दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यामंडु ओर्सी ने पदभार संभाल लिया। वामपंथी नेता, पूर्व मेयर और इतिहास के शिक्षक रहे 57 वर्षीय ओर्सी की सरकार ने वर्षों से चली आ रही आर्थिक स्थिरता को खत्म करके सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने निवर्तमान कंजरवेटिव राष्ट्रपति लुइस लैकेल पोउ की जगह ली है, जिनके पांच वर्ष के कार्यकाल में देश में कई मोर्चों पर समस्याएं देखी गई थीं।

एथेना लैंडर

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा

नासा की निजी एथेना लैंडर, जिसे इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा विकसित किया गया है, चंद्रमा की सतह पर उतर गया है, लेकिन इसकी स्थिति अनिश्चित है। लैंडिंग के कुछ पल बाद, टीम ने इंजर शटडाउन की पुष्टि की और अन्य कमांडों को स्वीकार किया, हालांकि लैंडर की स्थिति की अंतिम पुष्टि अभी भी लंबित है। यह नासा के वाणिज्यिक चंद्रमा पेलोड सेवाएं कार्यक्रम का हिस्सा है, जो वैज्ञानिक और संसाधन अवसरों से भरपूर क्षेत्र है। लैंडिंग साइट, मोंस माउंटन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 160 किलोमीटर दूर है, जो इस क्षेत्र में किसी भी अंतरिक्ष यान द्वारा अब तक की सबसे करीबी पहुंच है।

महरंग बलूच

नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुईं

बलूच कार्यकर्ता महरंग बलूच ने नोबेल पुरस्कार नामांकन की पुष्टि की है। उन्होंने बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों और जबरन गुमशुदगी पर वैश्विक ध्यान दिलाने का काम किया है। महरंग बलूच ने सोशल मीडिया पर कहा है कि नोबल पुरस्कार के लिए हुए इस नामांकन से बहुत सम्मानित महसूस कर रही हैं। बलूचिस्तान लंबे समय से मानवाधिकार उल्लंघनों और राज्य के दमन का शिकार रहा है। महरंग बलूच ने विशेष रूप से बलूच समुदाय के सदस्यों की जबरन गुमशुदगी के मुद्दे को उठाया है। बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी, राज्य की आलोचना करने वालों को हिरासत में लेना और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमले जैसे गंभीर आरोप लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। महरंग बलूच का नामांकन उन लोगों की आवाज को एक मंच प्रदान करता है जो इन घटनाओं से प्रताड़ित हैं और जिन्होंने न्याय की मांग की है। महरंग बलूच का नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की लड़ाई को एक वैश्विक मंच पर ले जाने का प्रयास है।

एक्स-37 बी

सीक्रेट मिशन से वापस लौटा

अमेरिकी सेना का मिनी स्पेस शटल, एक्स-37बी, 434 दिनों तक चले सीक्रेट मिशन को पूरा कर पृथ्वी पर वापस आया है। दिसंबर 2023 में नासा ने इसे कैनेडी स्पेस सेंटर से एक गुप्त मिशन के लिए लॉन्च किया था। स्पेस फोर्स के अधिकारियों के अनुसार इस मिशन ने वायुमंडलीय प्रतिरोध का उपयोग करके गति को धीमा करके कक्षा बदलने की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, जिससे ईंधन की बचत हुई।

सुनीता विलियम्स

अंतरिक्ष में रच रहीं इतिहास

सुनीता विलियम्स अपने साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ स्पेसएक्स के यान ड्रैगन पर सवार होकर लौटेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में दोनों यात्री पिछले 8 महीने से फंसे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि सुनीता पूरी तरह से सुरक्षित हैं और नासा उनकी सेहत को लेकर लगातार अपडेट देती रहती है। बिगड़ती सेहत के बावजूद इन आठ महीनों में सुनीता विलियम्स ने जो अनोखे रिकॉर्ड बनाए, सुनीता विलियम्स ने इन आठ महीनों में एक नहीं दो कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वह अब अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने वाली पहली महिला बन गई हैं। इसके अलावा सुनीता विलियम्स सबसे अधिक स्पेसवॉक करने वाली अंतरिक्ष यात्री भी बन गयी हैं।

अलेक्जेंडर डार्चियेव

अमेरिका में रूस के राजदूत होंगे

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलेक्जेंडर डार्चियेव को अमेरिका में नया राजदूत नियुक्त किया है। इस संबंध में हाल ही में डिक्री जारी की गई। डार्चियेव विदेश मंत्रालय के नॉर्थ अटलांटिक विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। डार्चियेव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विश्वसनीय सलाहकार रहे हैं वे वर्ष 1992 से विदेश मंत्रालय में काम कर रहे हैं।

निसार मिशन

इसरो-नासा का मिशन 20 मई को होगा लॉन्च

इसरो और नासा मिलकर नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार) मिशन को इसी साल लॉन्च करेंगे। मिशन को 20 मई को भारतीय समयानुसार प्रातः 6 बजे लॉन्च किया जा सकता है। निसार मिशन नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना है, जो पृथ्वी की सतह और बर्फ के अध्ययन के लिए बनाया गया है। यह दुनिया का पहला डुअल-फ्रीक्वेंसी रडार सैटेलाइट होगा, जो एल-बैंड और एस-बैंड रडार का उपयोग करेगा। इससे ग्लेशियरों, जंगलों, भूकंपों, कृषि, ज्वालामुखियों और भूमि उपयोग में हो रहे बदलावों की जानकारी मिलेगी। मिशन की लागत 1 अरब डॉलर (लगभग 85 अरब रुपये) से अधिक है।

स्मृति शेष

एक्टर साइमन फिशर का निधन

'हैरी पॉटर' सीरीज में भूत का किरदार निभाने वाले एक्टर साइमन फिशर बेकर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फिल्म 'हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन' में 'द फैट फ्रायर' के रोल से वो फेमस हुए थे। उन्होंने कई टीवी सीरीज में भी काम किया था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, गुना (म.प्र.)

निविदा विज्ञप्ति सूचना क्र. 11/2024-25 **दिनांक 11.03.2025**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग गुना के अंतर्गत निम्नांकित कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों से वेबसाइट **https:/mptenders.gov.in** के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें एवं अन्य अभिलेख टेण्डर प्रपत्र के साथ संलग्न है। जिन्हे वेबसाइट से डाउनलोड कर देखा जा सकता है। कार्य का विवरण एवं ऑनलाइन टेण्डर क्रय करने बिड सबमिशन करने का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. एवं कार्य का नाम - 1. लोनिवि संभाग गुना के अंतर्गत आने वाले मार्गों एवं पुल पुलियों पर जोनल पैच रिपेयर कार्य (कार्य की आवश्यकता अनुसार) वर्ष 2025-26

जिले का नाम	कार्य का प्रकार	ऑनलाइन टेण्डर क्रमांक	आमंत्रण क्रमांक	ठेके की अनु. राशि (लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	भौतिक रूप से एनवलप प्रस्तुत करने का कार्यालय (मूल अन्य दस्तावेज)
गुना	भवन अनुरक्षण	2025_PWDRB_408742_1	प्रथम	50.00	50000/-	5000/-	31.03.2026	अवश्यकता नहीं केवल टेण्डर पोर्टल पर उपलब्ध कार्यवें (http://mptenders.gov.in)

क्र. एवं कार्य का नाम - 2. लोनिवि उपखण्ड गुना के अंतर्गत आने वाले आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों की वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत, एम.ओ. डब्ल्यू. कार्य (कार्य की स्वीकृति एवं आवश्यकता अनुसार) एवं पुताई का कार्य वर्ष 2025-26

गुना	भवन अनुरक्षण	2025_PWDRB_408743_1	प्रथम	30.00	50000/-	5000/-	31.03.2026	- तदैव -

क्र. एवं कार्य का नाम - 3. लोनिवि उपखण्ड राघौगढ़ के अंतर्गत आने वाले आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों की वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत, एम.ओ. डब्ल्यू. कार्य (कार्य की स्वीकृति एवं आवश्यकता अनुसार) एवं पुताई का कार्य वर्ष 2025-26

गुना	भवन अनुरक्षण	2025_PWDRB_408744_1	प्रथम	25.00	50000/-	5000/-	31.03.2026	- तदैव -

क्र. एवं कार्य का नाम - 4. लोनिवि उपखण्ड चाचौड़ा के अंतर्गत आने वाले आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों की वार्षिक मरम्मत, विशेष मरम्मत, एम.ओ. डब्ल्यू. कार्य (कार्य की स्वीकृति एवं आवश्यकता अनुसार) एवं पुताई का कार्य वर्ष 2025-26

गुना	भवन अनुरक्षण	2025_PWDRB_408745_1	प्रथम	25.00	50000/-	5000/-	31.03.2026	- तदैव -

क्र. एवं कार्य का नाम - 5. सिविल लाइन गुना स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवासगृह क्र. 3 में बाउण्ड्रीवॉल की ऊंचाई बढ़ाना एवं गैरेज की विशेष मरम्मत कार्य।

गुना	भवन अनुरक्षण	2025_PWDRB_408746_1	प्रथम	4.24	8480/-	2000/-	01 माह वर्षाकाल सहित	- तदैव -

उपरोक्त निविदायें वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर दि. 20.03.2025 से ऑनलाइन भुगतान करने के उपरांत निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं बिड सबमिट करने की **अंतिम तिथि 05.04.2025 को समय 17:30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एनआईटी एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा पृथक से समाचार पत्रों मे प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-24295/50671/2025 **लोक निर्माण विभाग संभाग गुना**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग, छिन्दवाड़ा

E-mail : eepwd1chhind@mp.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्र. 10/व.ले.लि./2024-25/ **छिंदवाड़ा, दिनांक 11.03.2025**

निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने पर वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड की जा सकेंगी।

स.क्र. एवं कार्य का नाम - 1. दीघावानी से नवेगांव मार्ग का मजबूतीकरण कार्य लं. 3.20 कि.मी मय विद्युतीकरण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)

टेंडर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	ठेके की अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (लाख में)	समयावधि
408407	छिंदवाड़ा	सड़क कार्य	444.89	4,44,900/-	15,000/-	06 माह वर्षाऋतु सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम - 2. आयोजना मद अंतर्गत गोपालपुर से जमुनिया मार्ग का निर्माण कार्य लं. 3.00 कि.मी मय विद्युतीकरण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)

408408	छिंदवाड़ा	सड़क कार्य	364.33	3,64,400/-	15,000/-	06 माह वर्षाऋतु सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम - 3. छिन्दी सोनपुर मार्ग का मजबूतीकरण कार्य लं. 3.40 कि.मी मय विद्युतीकरण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)

408409	छिंदवाड़ा	सड़क कार्य	276.96	2,77,000/-	15,000/-	06 माह वर्षाऋतु सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम - 4. माहुलझिर अनहोनी मार्ग का मजबूतीकरण कार्य लं. 2.00 कि.मी मय विद्युतीकरण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)

408411	छिंदवाड़ा	सड़क कार्य	236.07	2,36,100/-	15,000/-	06 माह वर्षाऋतु सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम - 5. आयोजना मद अंतर्गत ग्वारा से सेहराडाना मार्ग का निर्माण कार्य लं. 2.50 कि.मी मय विद्युतीकरण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)

408412	छिंदवाड़ा	सड़क कार्य	211.50	2,11,500/-	15,000/-	06 माह वर्षाऋतु सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम - 6. वार्षिक संधारण मद से लो.नि.वि. उपसंभाग सौंसर अंतर्गत 03 मार्गों का शेष बी.टी. रिनुवल कार्य। 1. जाम सावली मंदिर मार्ग लं. 0.80 कि मी., 2. पांवुर्णा रजोलाकलां मार्ग लं. 2.00 कि.मी., 3. मारूड इटावा मार्ग लं. 4.00 कि.मी. (प्रथम आमंत्रण)

408797	पांवुर्णा	नवीनीकरण कार्य	17.31	34,700/-	2,000/-	02 माह वर्षाऋतु छोड़कर

कुल योग :- **1551.06 लाख**

टीप :- निविदा का विस्तृत विवरण (टेण्डर डाक्यूमेंट) म.प्र. शासन की निविदा पोर्टल **http://www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदा ऑनलाइन क्रय करने की **अंतिम तिथि 27.03.2025. समय 5:30 बजे तक** है। ऑनलाइन प्राप्त निविदा ऑफर को मान्य किया जायेगा। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्रो में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-24332/50675/2025 **लो.नि.वि.(भ/स) संभाग, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)**

एक जिला - एक उत्पाद

ओडीओपी-एक्सपो से मिलेगी लोकल उत्पादों को वैश्विक पहचान

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 'एक जिला-एक उत्पाद' हमारे कारीगरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में आयोजित 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) एक्सपो ने स्थानीय कारीगरों और किसानों के उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान किया। जीआईएस-भोपाल में 38 जिलों के विशिष्ट ओडीओपी उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें परंपरा और नवाचार का अनूठा संगम देखने को मिला। जीआईएस-भोपाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडीओपी को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त पहल बताया। उन्होंने कहा कि हर जिले का एक खास उत्पाद उसकी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान बन सकता है। ओडीओपी कार्यक्रम से लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ब्रांड बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआईएस-भोपाल में ओडीओपी-एक्सपो से हमारे स्थानीय उत्पादों, विशेष रूप से हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान बनाने का अवसर मिला है।

एक्सपो में ओडीओपी के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए, जिन्हें लाइव काउंटर और प्रोसेस काउंटर में विभाजित किया गया। लाइव काउंटर में बाग प्रिंट, जरी जरदोजी, बटिक प्रिंट, कालीन, चंदेरी साड़ी, बांस, बलुआ पत्थर और कपड़े की जैकेट जैसे आठ प्रमुख उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया को कारीगरों ने लाइव प्रदर्शित किया।

जीआईएस-भोपाल में आयोजन के दौरान विदेशी निवेशकों और उद्योगपतियों ने स्थानीय कारीगरों के हुनर को करीब से देखा और उनकी कार्यशैली को समझा। एक्सपो के 'कुम्हार पुरा' और 'टेक्निकल ज़ोन' के लाइव काउंटर भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने रहे।

खाद्य और कृषि उत्पादों को मिली नई पहचान

ओडीओपी-एक्सपो में खाद्य, मसाले और फलों से जुड़े 38 जिला विशिष्ट उत्पादों को उनके निर्माण प्रक्रिया के साथ प्रदर्शित किया गया। इन उत्पादों की खरीद और निर्यात के अवसर भी उपलब्ध कराए गए। साथ ही, निवेशकों ने विशिष्ट उत्पादों के सेंपल लिए, जिससे भविष्य में व्यापारिक संबंध स्थापित होने की संभावना बढ़ी।

मध्यप्रदेश में ओडीओपी के तहत विभिन्न जिलों के पारंपरिक, वस्त्र और कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें बुरहानपुर का केला, ग्वालियर के आलू आधारित उत्पाद और स्टोन टाइल्स, खरगोन की मिर्च उत्पाद, मंदसौर के लहसुन उत्पाद, नीमच के धनिया उत्पाद, सतना के टमाटर आधारित उत्पाद, मुरैना की गजक और सरसों उत्पाद, इंदौर के आलू आधारित उत्पाद, भोपाल के अमरूद उत्पाद, चंदेरी की साड़ियां, महेश्वर की साड़ियां और हथकरघा उत्पाद, टीकमगढ़ के मिट्टी शिल्प और हस्तशिल्प उत्पाद और धार के बाग प्रिंट शामिल हैं।

सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में ड्रॉप-आउट दर को कम करने के लिये ब्रिज कोर्स

भोपाल, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में अध्ययन के स्तर और दक्षता को सुधारने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ब्रिज कोर्स का संचालन कर रहा है। इसके लिये हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित विषय के 9 हजार 312 रिसोर्सपर्सन तैयार किये गये हैं। इनका प्रशिक्षण भोपाल के वाल्मी संस्थान में फरवरी माह में कराया जा चुका है। प्रदेश में 4 हजार 200 हाईस्कूल और 4 हजार 100 हायर सेकेण्डरी सरकारी स्कूल हैं। अब इन स्कूलों में हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित के एक-एक शिक्षक को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था मार्च माह से शुरू कर दी गई है। प्रदेश में लगभग 27 हजार शिक्षकों को ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ब्रिज कोर्स

प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक अप्रैल माह में और 16 जून से 20 जुलाई तक ब्रिज कोर्स का संचालन करेंगे। ब्रिज कोर्स का संचालन सभी सरकारी हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में होगा। इसके साथ ही इन 3 विषयों के अलावा विज्ञान एवं संस्कृत विषय की पढ़ाई भी इन बच्चों को कराई जायेगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल में लगने वाली ब्रिज कोर्स की समय-सारणी भी तैयार की है।

बेसलाइन टेस्ट

ब्रिज कोर्स के दौरान ही 5 और 12 अप्रैल को इन विद्यार्थियों का बेस लाइन टेस्ट अंग्रेजी, गणित और हिन्दी में लिया जायेगा। बेस लाइन टेस्ट पेपर 31 मार्च को स्कूल शिक्षा विभाग के 'विमर्श' पोर्टल पर अपलोड कर दिये जायेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। तय तिथियों में जो विद्यार्थी किन्हीं वजह से टेस्ट नहीं दे पायेंगे, उनके लिये अलग व्यवस्था की गई है। बेस लाइन टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधित शिक्षकों द्वारा उसी दिन किये जाने की व्यवस्था की गई है।

एंडलाइन टेस्ट

सरकारी हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में ब्रिज कोर्स की समाप्ति पर 20 जुलाई के बाद विद्यार्थियों की गुणवत्ता जांचने के लिये एंडलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था की जा रही है। यह टेस्ट 21 से 25 जुलाई के बीच होगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश दिये हैं। ब्रिज कोर्स की मॉनिटरिंग के लिये 3 स्तर पर राज्य, संभाग और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिमाह कम से कम 10 विद्यालयों में मॉनिटरिंग किये जाने के लिये कहा गया है। उनके इस कार्य में जिला परियोजना समन्वयक और विकासखंड शिक्षा अधिकारी मदद करेंगे।

जिला स्तर पर होगा मूल्यांकन

ब्रिज कोर्स संचालन के दौरान जिला स्तर के अधिकारी रेन्डमली कम से कम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं जिला स्तर पर बुलाकर पुनः मूल्यांकन करेंगे। इन बच्चों की दक्षता सुधार के लिये लोक शिक्षा संचालनालय स्तर पर सतत प्रयास किये जायेंगे।

वन संरक्षण के प्रति जागृति के लिये मनाते हैं - विश्व वानिकी दिवस

यूरोपीय कृषि संगठन की वर्ष 1971 में सम्पन्न आम बैठक में जंगलों को बचाए रखने के प्रमुख उद्देश्य से प्रतिवर्ष, 21 मार्च को "विश्व वानिकी दिवस" के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भी पेड़ों के महत्व को लेकर लोगों में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "विश्व वानिकी दिवस" मनाने पर अपनी सहमति दी, इसके बाद से ही प्रतिवर्ष दुनियाभर में 'विश्व वानिकी दिवस' 21 मार्च को मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन का उद्देश्य लोगों को पेड़ों के महत्व के प्रति जागरूक करना और उसके बचाव और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करना है। विश्व वानिकी दिवस के महत्व की यदि हम चर्चा करें तो यह दिवस इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आयोजन से लोगों में वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा होती है। इस आयोजन से वनों की सुरक्षा का माहौल बनता है और लोग वनों की रक्षा करने के बारे में सोचते हैं। इससे लोग वनों की अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इतना ही नहीं इस आयोजन से लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। विश्व वानिकी दिवस के जरिए लोगों को बताया जाता है कि जंगलों की कटाई के कारण दुनिया में ग्लोबल वॉर्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इस कारण से लोग जंगलों को बचाने का प्रयास करते हैं।

वानिकी के तीन तत्वों से अनुप्रेरित है यह दिवस

प्रकृति, पर्यावरण, वृक्षों के संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर- "विश्व वानिकी दिवस" मनाया जाता है। वानिकी के तीन महत्वपूर्ण तत्वों- वनों की सुरक्षा, वन विस्तार के माध्यम से वन उत्पादों में बढ़ोत्तरी और समृद्ध वनस्पतियों, वृक्षों और जीवों को वापस लाने और उन्हें संरक्षित करने के बारे में लोगों में रुचि बढ़ाने तथा इस सम्बन्ध में जानकारियां देने के लिए 21 मार्च "विश्व वानिकी दिवस" के रूप में चुना गया। वस्तुतः वानिकी के इन्हीं तत्वों से अनुप्रेरित है विश्व : वानिकी दिवसा विशेषज्ञों की मानें तो जंगल एक ऐसा भू-क्षेत्र है जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक होता है और वस्तुतः एक ऐसा जीवित समुदाय होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे, कीट-पतंगे, जीव-जंतु एक-दूसरे पर निर्भर होकर अपना जीवन बिताते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि समय रहते पर्यावरण तथा पेड़-पौधों और वृक्षों को बचाने पर ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब समस्त प्रकृति एवं सभी जीव खतरे में पड़ जाएंगे। पर्यावरणविदों के अनुसार पिछले कुछ दशकों में व्यावसायिक मुनाफे के लिए जिस तरह से वनों की अंधाधुन्ध कटाई हुई है उससे विश्व को ग्लोबल वॉर्मिंग, जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर के पिघलने जैसी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस परिवर्तन से ऑक्सीजन की कमी होगी, वहीं किसी वयस्क व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, वह नहीं मिलने के कारण मनुष्य का जिंदा रहना असम्भव हो जाएगा।

वन एवं जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण है मध्यप्रदेश का अवदान

वसुधैव कुटुम्बकम् की संस्कृति वाला हमारा देश सम्पूर्ण जीव-जगत को अपना कुटुम्ब ही मानता है। हम सदियों से वनों, पहाड़ों और नदियों को पूजते चले आ रहे हैं। पूर्वजों की इस परम्परा को सहेजे जाने के लिए जैव-विविधता का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिये वन जीवन को सहेजकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। वन एवं जैव-विविधता संरक्षण की

इसी कड़ी में मध्यप्रदेश का अवदान भी महत्वपूर्ण रहा है, मध्यप्रदेश ने देश में सबसे पहले वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। प्रदेश में वर्ष 1973 में वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। मध्यप्रदेश, आज भी देश में वन और वृक्ष आवरण में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। मध्यप्रदेश कुल वन और वृक्ष आवरण 85 हजार 724 वर्ग किलोमीटर और वनावरण 77,073 वर्ग किलोमीटर के साथ देश का अग्रणी राज्य है। यहां वनों को प्रकृति ने

अकूत सम्पदा का वरदान देकर समृद्ध किया है। प्रदेश में 30.72 प्रतिशत वन क्षेत्र है जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30 प्रतिशत है। यहां कुल वन क्षेत्र 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर (94 लाख 68 हजार 900 हेक्टेयर) है। प्रदेश में 24 अभयारण्य, 11 नेशनल पार्क और नौ टाईगर रिजर्व हैं, जिसमें कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण में लैंडमार्क बन गये हैं।

संयुक्त वन प्रबंधन में भी अग्रणी है मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए जन सहयोग प्राप्त करने के लिए वनों एवं उनके आसपास निवास करने वाले समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की भी अहम् भूमिका होती है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी संयुक्त वन प्रबंधन हेतु एक संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया, जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है। सघन वन क्षेत्रों में वनखण्ड सीमा की 5 किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली संयुक्त वन प्रबंधन समिति को "वन सुरक्षा समित" कहा जाता है। वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, चराई एवं अग्नि से क्षेत्र की सुरक्षा करती है तथा इसकी एवज में उन्हें आवंटित क्षेत्र से समस्त लघु वनोपज, रॉयल्टी मुक्त निस्तार एवं काष्ठ की बिक्री से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत लाभांश दिये जाने का प्रावधान है। बिगड़े वन क्षेत्रों में वनखण्ड की सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली समिति को "ग्राम वन समिति" कहा जाता है। ग्राम वन समिति के सहयोग से पुनर्स्थापित होने पर आवंटित वन क्षेत्र से प्राप्त होने वाली समस्त लघु वनोपज एवं काष्ठ अनुपातिक विदोहन व्यय घटाकर ग्राम वन समिति को प्रदाय करने का प्रावधान है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए गठित राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य बफर क्षेत्रों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में "ईको विकास समिति" गठित करने का प्रावधान है। इन समितियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान का कार्य ईको विकास कार्यक्रम के तहत किया जाता है। वन क्षेत्र की स्थिति के अनुसार, संयुक्त वन प्रबंधन समिति का 5 वर्ष की अवधि के लिए गठन किया जाता है। अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, यथा संभव, ग्रामसभा में इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

सामाजिक वानिकी के लिये हैं प्रदेश में सामाजिक वन वृत्त

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रत्येक कृषि जलवायु प्रक्षेत्र में क्रमशः बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, खण्डवा, रतलाम, रीवा, सागर एवं सिवनी में सामाजिक वानिकी वन वृत्त स्थापित किए गये हैं। सामाजिक वानिकी रोपणियों से वर्ष 2023 के रोपण हेतु लगभग 4.64 करोड़ पौधे निर्वर्तित किये गये थे। विभाग से बाहर गैर वन क्षेत्रों में 23.54 लाख पौधों का प्रदाय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में गैर वन क्षेत्रों में पौधों के विक्रय से 9.56 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2024 के रोपण हेतु सामाजिक वानिकी रोपणियों में 6.70 करोड़ पौधे उपलब्ध करवाये गये हैं। विभागीय रोपणों हेतु सामाजिक वानिकी रोपणी में 55,000 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट भी तैयार किया गया जो क्षेत्रीय वनमंडलों को वर्ष 2024 के रोपण हेतु प्रदाय किया गया। विस्तार वानिकी योजना के अंतर्गत वर्षा ऋतु 2023 में क्षेत्रीय वनमण्डलों के माध्यम से विभिन्न जिलों में गैर वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के 9.90 लाख पौधों का रोपण किया गया था। मध्यप्रदेश में भी गुजरात मॉडल की तर्ज पर प्रदेश में 4 स्थलों उज्जैन, सतना, छतरपुर एवं भोपाल में सांस्कृतिक वन स्थापित किये गये गये हैं।

वन्यजीव कॉरिडोर बनने से घटेगा मानव और वन्यजीव संघर्ष

बाघ एवं तेंदुआ स्टेट का सम्मान मध्यप्रदेश को मिला हुआ है। हमारे प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त खुले वनों में भी 30 प्रतिशत से अधिक बाघ विचरण कर रहे हैं। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। मानव-वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिये विशेष वन्यजीव कॉरिडोर बनाये गये हैं। साथ ही 14 रीजनल रेस्क्यू स्क्वॉड और एक राज्य स्तरीय रेस्क्यू स्क्वॉड का गठन किया गया है। वन्य जीवों को मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिए संवेदनशील क्षेत्रों से रेस्क्यू कर संरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जायेगा, जिससे वन्यजीवों का प्रबंधन एवं संरक्षण अधिक प्रभावी रूप से हो सकेगा। इन संघर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 80 प्रतिशत जनहानि, 15 हजार पशु हानि होती है और 1300 नागरिक घायल होते हैं। मानव-वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिये शासन ने जनहानि के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया है। इन प्रकरणों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिवस के अंदर क्षति-पूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

प्रदेश में हाथियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक एलीफेंट-टॉस्क फोर्स का गठन भी किया गया है। हाथी प्रबंधन के लिये योजना तैयार की जा रही है। इसमें एआई तकनीक के उपयोग से स्थानीय समुदायों की सहभागिता को भी प्रबंधन में सम्मिलत किया जा रहा है। हाथी विचरण क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह एक सफल प्रयोग साबित होगा।

- राजा दुबे
(लेखक, जनसंपर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं)

मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स सेक्टर में नए निवेश की बढ़ी संभावनाएं - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण यह प्रदेश उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम के व्यापार मार्गों को सुविधाजनक रूप से जोड़ते हुए एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहा है। आधुनिक बुनियादी ढांचे, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और उद्योग समर्थक नीतियों के कारण प्रदेश निवेशकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में की जा रही रणनीतिक पहलों से मध्यप्रदेश अब सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं, बल्कि पूरे भारत की आपूर्ति श्रृंखला का एक मजबूत आधार बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के हब के रूप में उभर रहा है। अपनी भौगोलिक स्थिति, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण यह प्रदेश निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं इसे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं।

बेहतर सड़कों और कॉरिडोर से लॉजिस्टिक्स को नई दिशा

प्रदेश में लॉजिस्टिक्स को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का तेजी से विस्तार किया गया है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, उत्तर-दक्षिण फ्रेट कॉरिडोर और भारतमाला परियोजना प्रदेश को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रही हैं। इंदौर और भोपाल में विकसित हो रहे मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) व्यापार को आसान और लागत प्रभावी बना रहे हैं।

हवाई मार्ग से निर्यात और उद्योग को नई गति

प्रदेश के छह प्रमुख हवाई अड्डों पर एयर कार्गो सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ी ताकत मिल रही है। रीवा हवाई अड्डे के चालू होने से व्यापार और औद्योगिक परिवहन को नई रफ्तार मिली है। फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों को अब कम समय में बेहतर लॉजिस्टिक्स सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

जल जीवन मिशन को नई गति देगा मध्यप्रदेश का बजट

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रस्तुत वर्ष 2025-26 का बजट प्रदेश के समग्र विकास का प्रतिबिंब है। हर वर्ग की उन्नति को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस बजट में जल जीवन मिशन के तहत 17,136 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। यह कदम न केवल जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि जल संरक्षण और अधोसंरचना विकास को भी नया आयाम देगा।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि यह बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट दूर होगा, बल्कि महिलाओं और बच्चों को होने वाली असुविधा से भी राहत मिलेगी। स्वच्छ जल की सहज उपलब्धता से ग्रामीण जीवनस्तर में व्यापक सुधार आएगा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में कमी आएगी।

प्रदेश के जल संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए जल आपूर्ति से जुड़ी अधोसंरचनाओं को और मजबूत किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में घर-घर नल से जल पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को इस बजट से और अधिक गति मिलेगी। इस वर्ष जल संरक्षण और जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए किए गए प्रावधान राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे।

युवाओं के नवाचार को लोकल से ग्लोबल बनाने में मददगार साबित होगी मध्यप्रदेश की नई स्टार्टअप नीति 2025

भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्यप्रदेश की नई स्टार्टअप नीति जारी की गई। इस नीति के केन्द्र में विरासत के साथ विकास का मूल मंत्र शामिल है। भारत में पुरातन समय से नवाचार होते आये हैं। यह नवाचार शोध, शिक्षा और अनुसंधान के द्वारा समूचे विश्व तक पहुंचे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विरासत के साथ विकास की संभावनाओं को आकार दे रहे हैं। मध्यप्रदेश का अपना गौरवशाली इतिहास है। विविधता से समृद्ध और विरासत से संपन्न हृदय प्रांत मध्यप्रदेश उद्यमशीलता और नवाचारों का केन्द्र रहा है। प्रदेश की इसी विशेषता को नये स्वरूप के साथ नई स्टार्टअप नीति में तराशने की कवायद चल रही है। नवीन नीति में शिक्षा संस्थान, इनक्यूबेशन सेंटर, स्थानीय लोग और निवेशक मिलकर एक समृद्ध इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। प्रदेश में इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा स्टार्टअप को आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। विविधता से भरे मध्यप्रदेश में यहां के युवा, क्षेत्रीयजनों और क्षेत्र विशेष की विशेषताओं के साथ स्टार्टअप को खड़ा करने में लगे हैं। प्रदेश के स्टार्टअप क्षेत्र की इस यात्रा को लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाने के लिए नई स्टार्टअप नीति कारगर साबित हो सकती है। इस नीति का लक्ष्य है, मध्यप्रदेश को वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करना है, जिससे नवाचार, पूंजी तथा रोज़गार सृजन और सहायक इकोसिस्टम को प्रोत्साहन संभव हो।

उद्देश्य

- अधिमान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 तक बढ़ाना।
- 100 करोड़ रुपये के सीड कैपिटल फंड की स्थापना।
- 1.10 लाख तक रोज़गार सृजित करना।
- 500 से अधिक स्टार्टअप्स को मार्केट में निवेश योग्य बनाना।
- मेगा इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना।

स्टार्टअप नीति के प्रमुख स्तम्भ

वित्त पोषण
- सीड फंड अनुदान।
- स्टार्टअप कैपिटल फंड।
- प्राप्त निवेश तथा ऋण सहायता।

बाजार तक पहुंच और मेंटरिंग
- स्टार्टअप एक्सेलेरेशन कार्यक्रम।
- ग्रैंड चैलेंज और हैकथॉन।

उत्पाद आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा
- रोज़गार सृजन सहायता।
- कौशल विकास सहायता।
- विद्युत शुल्क सहायता।
- एमएसएमई विकास नीति का लाभ।

संस्थागत सहयोग
- स्टार्टअप सलाहकार परिषद की स्थापना।
- सरलीकृत एवं सशक्त पोर्टल और ऐप।
- हेल्प लाइन।

नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन
- पेटेंट प्रोत्साहन।
- टिंकरिंग लैब्स की स्थापना।
- आंत्रप्रेन्योर-इन-रेसिडेंस (ईआईआर)।

अधोसंरचना सहयोग
- मेगा इनक्यूबेटर की स्थापना।
- नवीन इनक्यूबेटर हेतु पूंजी अनुदान।
- इनक्यूबेटर हेतु उन्नयन अनुदान।

क्या प्रावधान है नीति में

सीड फंड अनुदान

चयनित इनक्यूबेटरों के माध्यम से 30 लाख रुपये तक की सीड फंड सहायता।

स्टार्टअप कैपिटल फंड

अल्टरनेट इनवेस्टमेंट फंड (एआईएफ) के सहयोग से 100 करोड़ रुपये का स्टार्टअप कैपिटल फंड (1:1 योगदान) से प्रदेश के ग्रोथ स्टेज वाले स्टार्टअप में निवेश।

ब्याज अनुदान सहायता

स्टार्टअप को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत बैंकों के माध्यम से कोलेटरल मुक्त ऋण पर ब्याज अनुदान और गारंटी शुल्क कवरेज प्रदान करना। (5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान, गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति, बैंकों के माध्यम से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए)।

प्रोटोटाइप, उत्पाद विकास अनुदान

किसी भी राज्य, केंद्र सरकार के कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संगठन के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण, प्रोटोटाइप, उत्पाद विकास, डिजाइन और ब्रांडिंग आदि के लिए 15 लाख रुपये तक की कुल सहायता प्रदान की जायेगी।

लीज रेंटल सहायता

3 वर्षों के लिए ऑफिस इकाई के किराए पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति माह।

प्राप्त निवेश, ऋण पर सहायता

सेबी, आरबीआई पंजीकृत संस्थान, राज्य, केंद्र सरकार की योजना से प्राप्त प्रति निवेश, ऋण (अनुदान को छोड़कर) पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम 18 लाख रुपये प्रदाय करना। स्टार्टअप के जीवनकाल के दौरान अधिकतम 4 बार (कुल 72 लाख रुपये तक)।

बाजार तक पहुंच और मेंटरिंग

मध्यप्रदेश स्टार्टअप एक्सेलरेशन कार्यक्रम

इक्यूबेटर्स के माध्यम से न्यूनतम 12 सप्ताह का एक्सेलेरेशन कार्यक्रम। प्रत्येक कार्यक्रम हेतु चयनित इनक्यूबेटर को अधिकतम 15 लाख रुपये की सहायता।

- **ग्रैंड चैलेंज और हैकाथॉन**

प्रति स्टार्टअप 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान, अधिकतम 4 स्टार्टअप। हैकाथॉन के लिए प्रति समाधान 5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जायेगी।

- **ऑनलाइन विज्ञापन सहायता**

विज्ञापन व्यय के लिए अधिकतम रुपये 3 लाख की सहायता की जायेगी।

- **आधोसंरचना सहयोग- इनक्यूबेटर मेगा इनक्यूबेटर की स्थापना**

मध्यप्रदेश के एक प्रमुख शहर में पीपीपी मोड में मेगा इनक्यूबेटर की स्थापना की जायेगी।

- **अधोसंरचना का विकास**

नवीन इनक्यूबेटर स्थापना पर सहायता- न्यूनतम 5000 वर्गफुट का इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए शासकीय होस्ट संस्थान हेतु 100 प्रतिशत एवं प्राईवेट होस्ट संस्थान हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख रुपये का प्रावधान।

- **अधोसंरचना उन्नयन**

उन्नयन सहायता- 50 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख तक, पॉलिसी अवधि के दौरान दो बार प्रदाय का प्रावधान प्रदाय।

- **विनिर्माण केन्द्रित इनक्यूबेटर के लिए भूमि आवंटन**

विभाग के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूमि आवंटन नियमों के तहत उद्योगों के समान दरों पर उत्पाद केन्द्रित इनक्यूबेटर के लिए भूमि का आवंटन।

संस्थागत सहयोग

- **राज्य स्तरीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद**

राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जीवंत और सुदृढ बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु मार्गदर्शन देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद का गठन।

समर्पित हेल्पलाइन पोर्टल

- इसमें मोबाइल ऐप, चैटबॉट, ऑनलाइन ट्रैकिंग, पोर्टल के माध्यम से वित्तीय सहायता, हेल्पलाइन शामिल हैं।

स्टार्टअप के रिवाइवल हेतु सहयोग
- इनक्यूबेटर्स और निजी क्षेत्र के भागीदारों के सहयोग से, संघर्षरत स्टार्टअप को कानूनी, वित्तीय और विपणन परामर्श।

प्राथमिकता क्षेत्र
- प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्रों में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, डीप टेक, सर्कुलर इकोनॉमी, न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी, एवीजीसी एक्सआर, मोबिलिटी, बायोटेक और लाइफ साइंस, पर्यटन, बायोप्रिंटिंग, ऑर्गेनॉइड्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन ऑग्मेंटेशन, बायोडायनामिक्स, ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (बीसीआई), क्वांटम टेक्नोलॉजी आदि शामिल हैं।

नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा

- **पेटेंट सहायता**

घरेलू पेटेंट पर 5 लाख रुपये तक, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट पर 20 लाख रुपये तक सहायता।

- **टिंकरिंग लैब्स की स्थापना**

प्रदेश के अधिकाधिक विद्यालयों में भारत सरकार के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना।

- **आंत्रप्रेन्योर-इन-रेसिडेंस (ईआईआर) सहायता**

प्रत्येक स्टार्टअप को 12 महीने तक की अवधि के लिए 10 हजार रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।

विनिर्माण आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा

- **प्रशिक्षण आधारित प्रतिपूर्ति**

कौशल विकास के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति सहायता अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिए प्रति नए कर्मचारी प्रति वर्ष 13,000 रुपये की दर से 3 वर्षों के लिए प्रदान की जायेगी।

- **रोज़गार सृजन सहायता**

प्रति कर्मचारी 5000 रुपये की सहायता, अधिकतम 3 वर्ष और 25 कर्मचारियों के लिए प्रदाय।

विद्युत टैरिफ हेतु प्रतिपूर्ति विद्युत शुल्क में छूट

2 रुपये प्रति यूनिट की प्रतिपूर्ति एवं शुल्क में छूट 3 वर्ष के लिए।

मध्यप्रदेश नई स्टार्टअप नीति-2025 में स्टार्टअप तंत्र से जुड़े सभी पक्षों को सबल और सुचारू किये जाने का प्रयास है। इससे स्टार्टअप को आधारभूत सहयोग से लेकर बाजार पहुँच तक का संबल मिलेगा। नवचारों के साथ प्रदेश में स्टार्टअप की संभावनाएं विकसित होंगी। आने वाले समय में मध्यप्रदेश स्टार्टअप हब के रूप में उभरेगा। जो प्रदेश की समृद्धि को नई ऊंचाईयां प्रदान करेगा। इस नीति में स्टार्टअप की आवश्यकता अनुसार विविध चरणों में सहायता का प्रावधान है। इन चरणों में स्टार्टअप आईडीएशन वेलीडेशन, अर्ली स्टेज तथा ग्रोथ शामिल है। इससे स्टार्टअप सशक्त होने के साथ नवाचार के लिये सक्रिय होंगे।

- हितेश शर्मा
(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

प्रदेश में 30 मार्च से चलेगा 'जल गंगा संवर्धन अभियान'

भोपाल, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने प्रमुख अभियंता जल संसाधन कार्यालय के सभाकक्ष में अभियान की तैयारियों के संबंध में बैठक को संबोधित किया। श्री सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संकल्प है कि हर घर स्वच्छ पेयजल और खेती के लिए हर खेत तक पानी पहुंचे। इसके लिए प्रदेश में केन-बेतवा और पार्वती - कालीसिंध - चंबल परियोजनाओं के बाद ताप्ती मेगा बेसिन परियोजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रदेश में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तालाब एवं अन्य जल स्रोतों के उन्नयन, विकास, गहरीकरण, जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने और उनके आसपास पौधा-रोपण आदि के उद्देश्य से प्रदेश में 30 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक 'जल गंगा संवर्धन अभियान' चलाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का जनता से आह्वान किया।

जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि जल संसाधन विभाग में प्रदेश में 32 वृहद, 120 मध्यम एवं 5 हजार 800 लघु जल संरचनाएं हैं। इनमें बनाए गए बांधों की नहर प्रणाली 40 हजार किलोमीटर की है जिनमें 16 हजार किलोमीटर पक्की और 24 हजार किलोमीटर कच्ची नहरें हैं। इन नहरों से सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं की आवश्यक मरम्मत, सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य किया जाना है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में जल संरक्षण एवं संवर्धन की समृद्धशाली परंपरा रही है। यहां की चंदेल कालीन जल संरक्षण प्रणाली न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही है। जल संसाधन संभाग छतरपुर में 44, टीकमगढ़ में 71 और पन्ना में 5 चंदेल एवं बुंदेलकालीन तालाब हैं। अभियान के अंतर्गत इन सभी का संरक्षण किया जाना है।

जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिए कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए छोटी-छोटी योजनाएं बनाकर कार्य कराया जाए। आगामी बारिश के पूर्व प्रदेश के सभी पुराने बांधों एवं जल स्रोतों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। इसके लिए गत वर्ष में जिन-जिन तालाबों एवं जल स्रोतों में क्षति हुई उनकी सूची बनाई जाए तथा उन जल स्रोतों का विशेष ध्यान रखा जाए। बांधों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जाएं।

जॉब अलर्ट

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) अहमदाबाद

पद का नाम - प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वित्त एवं लेखा अधिकारी, पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, संपदा एवं सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, अतिथि गृह एवं छात्रावास पर्यवेक्षक, वैज्ञानिक/तकनीकी पर्यवेक्षक (ग्रेड-I एवं ग्रेड-II), प्राशासनिक अधिकारी, कुलसचिव के सचिव, जनसंपर्क अधिकारी, तकनीकी सहायक (कम्प्यूटर अनुभाग), लेखाकार, रिसेप्शनिस्ट सह टेलीफोन ऑपरेटर, सहायक ग्रेड-I, सहायक ग्रेड-II, कनिष्ठ तकनीकी सहायक।

पदों की संख्या - 29

योग्यता - पदानुसार

अंतिम तिथि - 23 मार्च, 2025

वेबसाइट - https://niperahm.ac.in

महानिदेशक असम राइफल्स का कार्यालय

पद का नाम - धार्मिक शिक्षक, रेडियो मैकेनिक, लाइनमैन फील्ड, इंजीनियर उपकरण मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, अपहोल्स्टर, व्हीकल मैकेनिक फिटर, नक्शानवीस, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल, प्लंबर, ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन, फार्मासिस्ट, एक्स-रे असिस्टेंट, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, सफाई

पदों की संख्या - 215

योग्यता - पदानुसार

अंतिम तिथि - 22 मार्च, 2025

वेबसाइट - https://assamrifles.gov.in

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरै

पद का नाम - प्रोफेसर, अपर प्रोफेसर, सह प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर

पदों की संख्या - 39

योग्यता - चिकित्सा शिक्षा में एमडी/एमएस की डिग्री तथा भारतीय चिकित्सा आयोग द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं

अंतिम तिथि - 25 मार्च, 2025

वेब. - https://aiimsmadurai.edu.in

हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान

पद का नाम - वैज्ञानिक

पदों की संख्या - 12

योग्यता - संबंधित विषय में पीएचडी की उपाधि

अंतिम तिथि - 24 मार्च, 2025

वेबसाइट - https://www.ihbt.res.in

उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक)

पद का नाम - वैज्ञानिक सी

पदों की संख्या - 10

योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रथम श्रेणी में बीई/बीटेक/एमसीए की उपाधि।

अंतिम तिथि - 23 मार्च, 2025

वेबसाइट - https://careers.cdac.in

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमि.

पद का नाम - सहायक गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी

पदों की संख्या - 97

योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रासायन विज्ञान या समकक्ष विषय में मास्टर डिग्री

अंतिम तिथि - 21 मार्च, 2025

वेबसाइट - https://iocl.com

रक्षा मंत्रालय (नौसेना) नौसेना पोत मरम्मत यार्ड कोच्चि

पद का नाम- ट्रेड प्रशिक्षु- कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर वाहन (एमएमवी), मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन, टर्नर, वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक), इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फाउंड्री मैन, शीट मेटल वर्कर, ड्राफ्ट्समैन (सिविल, मैकेनिकल), सचिवालय सहायक, इलेक्ट्रोप्लेटर, प्लंबर, मैकेनिकल डीजल, दर्जी (सामान्य), मैकेनिक रेडियो और रडार एयरक्राफ्ट, पेंटर (सामान्य), शिपराइट (लकड़ी)

पदों की संख्या - 240

योग्यता- पदानुसार

अंतिम तिथि - उल्लेखित नहीं

वेब. - https://cochinshipyard.in

पंजाब नेशनल बैंक

पद का नाम - ऑफिसर (क्रेडिट), ऑफिसर (इंडस्ट्री), मैनेजर (आईटी), सीनियर मैनेजर (आईटी), मैनेजर (डाटा साइंटिस्ट), सीनियर मैनेजर (डाटा साइंटिस्ट), मैनेजर (साइबर सिक्योरिटी), सीनियर मैनेजर (साइबर सिक्योरिटी)

पदों की संख्या - 350

योग्यता - पदानुसार

अंतिम तिथि - 24 मार्च, 2025

वेब. - https://www.pnbindia.in

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पद का नाम - ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्निशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस

पदों की संख्या - 135

योग्यता - ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए बीई या अन्य समकक्ष इंजीनियरिंग डिग्री, टेक्निशियन अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग या तकनीकी में डिप्लोमा तथा ट्रेड अप्रेंटिस के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा

अंतिम तिथि - 23 मार्च, 2025

वेबसाइट - https://neepco.co.in

एडमिशन अलर्ट

राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, नागपुर

पाठ्यक्रम का नाम - पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (बिजनेस मैनेजमेंट)

योग्यता- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री

अंतिम तिथि - 31 मार्च, 2025

वेबसाइट - https://curaj.ac.in

भारतीय विज्ञान संस्थान

पाठ्यक्रम का नाम - अनुसंधान कार्यक्रम (पीएचडी/ एमटेक), बाह्य पंजीकरण कार्यक्रम (ईआरपी) (पीएचडी/ एमटेक), इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम कार्यक्रम (एमटेक/एम.डेस/एम.एमजीटी), विज्ञान में पाठ्यक्रम कार्यक्रम, एकीकृत पीएचडी कार्यक्रम, गणित तथा कम्प्यूटिंग में बीटेक और चार वर्षीय बीएस (अनुसंधान)।

योग्यता- संबंधित विषय में न्यूनतम स्नातक उपाधि।

अंतिम तिथि - 23 मार्च, 2025

वेबसाइट - https://iisc.ac.in

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

हमारा जिला श्योपुर

प्राकृतिक संसाधनों की विविधताओं से परिपूर्ण है श्योपुर जिला

मध्यप्रदेश विविधता से समृद्ध है। प्रदेश के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता, क्षमता और दक्षता है। यहां का प्रत्येक जिला अपना इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, उपज और अन्य क्षेत्रीय विशेषताएं लिए हुए है। 'रोज़गार और निर्माण' के 'हमारा जिला' स्तम्भ में हम मध्यप्रदेश के एक जिले से आपको परिचित करवाते हैं। इस अंक में प्रस्तुत है श्योपुर जिले का परिचय-

श्योपुर जिला चंबल संभाग में शामिल है, जिसका जिला मुख्यालय सीप नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। मान्यता है कि जयपुर राजघराने के सामंत गौड़ राजपूत के प्रमुख इंद्रसिंह द्वारा शहर और उसके किले की स्थापना ई. 1537 में की गई थी। गौड़ राजपूत भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए यहां कई शिव मंदिरों का निर्माण किया गया। 1818 ई. में ग्वालियर की संधि के बाद यहां के किले पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। स्वतंत्रता के बाद यह मध्यप्रदेश राज्य का हिस्सा बना। यह जिला मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। यह पूर्व में मध्यप्रदेश के शिवपुरी, पश्चिम में राजस्थान के कोटा, उत्तर में मुरैना, ग्वालियर एवं दक्षिण में राजस्थान के कोटा जिले से जुड़ा हुआ है। श्योपुर, ग्वालियर नैरोगेज लाइन से भी जुड़ा हुआ है। यहां से विजयपुर, कराहल और बड़ौदा के लिए परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं। यहीं से राजस्थान के सवाई माधोपुर के लिये भी परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं। पालपुर (कूनो) राष्ट्रीय उद्यान मुख्य पर्यटन स्थल है। ककेता जलाशय भी इसी जिले में है। यह जिला लकड़ी के फर्नीचर के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। यहां सागौन की लकड़ी से दरवाजे, खिड़की आदि बहुत ही खुबसूरत ढंग से बनाए जाते हैं। जिले में मुख्य रूप से चंबल, सीप और कूनो नदियां बहती हैं। चंबल नदी इंदौर से होते हुए दक्षिण-पूर्व मध्यप्रदेश की ओर बहती है। यहां से प्रति वर्ष सावन के महीने में गोवर्धन (मथुरा), कैलादेवी (करोली), श्रीजी (दिग्गीपुरी राजस्थान), त्रिनेत्र गणेश जी (सवाईमाधोपुर) आदि जिलों में पदयात्री जाते हैं। सड़क मार्ग सभी तहसील मुख्यालयों से जुड़ा हुआ है। श्योपुर की कराहल तहसील में प्रदेश की सहरिया जनजाति निवास करती है। इसके अलावा श्योपुर जिले में मत्स्य राजवंशी क्षत्रिय जो रावत मीणा कहलाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। इन्हें भगवान विष्णु के प्रथम मत्स्य अवतार से जोड़कर भी देखा जाता है। जिले की सबसे बड़ी तहसील विजयपुर है, जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र शिवपुर और विजयपुर आते हैं, शिवपुर और विजयपुर में नगर पालिका परिषद भी हैं।

उत्पादन

गेहूं - गेहूं जिले का प्रमुख खाद्यान्न है। यहां उत्पादित सरसों, तेल निकालने के लिये उपयोगी है। श्योपुर जिले में पाइप, मुखौटे, खिलौने, दरवाजे, स्टैंड, खिड़कियां, लकड़ी के स्मारक, फूलों के फूलदान, बेडपोस्ट और पालना आदि निर्माण के कुल 156 लघु उद्योग चल रहे हैं।

प्रमुख आकर्षण तथा दर्शनीय स्थल

कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डोब कुंड, मोरडूंगरी, त्रिवेणी संगम पर स्थित रामेश्वर, श्योपुर दुर्ग स्थित सहरिया जनजाति का संग्रहालय, विजयपुर का किला, दर्शनीय स्थल, ध्रुव कुंड, उतनवाड गांव के शिवनाथ निमोदा का मठ, जिसे कमलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पनवारा देवी का मंदिर, सिरोनी हनुमान मंदिर, चंद्रसागर जल मंदिर बड़ौदा, क्षेत्रपाल जैनी का मंदिर, पार्वती माता मंदिर जाटखेड़ा, छिमछिमा हनुमान मंदिर विजयपुर, गुसाई जी महाराज

मंदिर ग्राम पंचायत पांडोली आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।

कूनो राष्ट्रीय उद्यान - श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। यह ऐतिहासिक स्थल भी है। प्रदेश के उत्तर-पश्चिम में राजस्थान की सीमा के करीब स्थित है, इसलिए कूनो

के जंगल में राजस्थान की वनस्पति का प्रभाव देखा जा सकता है। यह शेर और चीता पुनर्वास परियोजना के कारण विशेष महत्व रखता है। चीता प्रोजेक्ट के पहले चरण में 17 सितंबर, 2022 को नामीबिया से लाये गये 8 चीते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को समर्पित किये। उसके बाद दूसरे चरण में 18 फरवरी, 2023 को 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। कूनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य 344.686 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और मध्यप्रदेश के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इस अभयारण्य में स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों की विशाल समृद्धि और विविधता है। वर्ष 2018 में इसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया जो इस वन के लिए गौरव की बात है। इस नेशनल पार्क में संरक्षित क्षेत्र की वनस्पति में एनोगेसस पेंडुला वन और झाड़ी, बोसवेलिया और बुटिया वन, शुष्क सवाना वन और घास के मैदान और ऊष्णकटिबंधीय नदी के जंगल शामिल हैं। प्रमुख वृक्ष प्रजातियां बबूल केचु, सलाई बोसवेलिया सेराटा, तेंदु डायस्पायरोस मेलानोक्सीलॉन, पलाश बुटिया मोनोस्पर्मा, ढोक एनोजिसस, लैटिफोलिया, बबूल ल्यूकोफ्लोओ, जिजिफस मॉरिटियाना और जिजिफस जाइलोपाइरस हैं। प्रमुख झाड़ीदार प्रजातियों में ग्रेविया फ्लेवेस्केंस, हेलिकटेरस आइसोरा, होपबश विस्कोसा और विटेक्स नेगुंडो शामिल हैं।

डोब कुंड - डोब कुंड एक गांव है जो श्योपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। डोब कुंड में दो पुराने खंडहर मंदिरों की खोज की गई थी जिनमें दो शिलालेख थे। इनमें से एक मंदिर हरद जौरी है और दूसरा दिगंबर संप्रदाय के जैन तीर्थंकरों का है। 59 रेखाओं से युक्त प्रमुख शिलालेख को एक स्तंभ में अंकित किया गया है।

ध्रुव कुंड - श्योपुर में चंबल नहर के पास ध्रुव कुंड स्थित है जिसमें दो कुंड हैं एक गर्म पानी का और दूसरा ठंडे पानी का है। मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। अन्य दर्शनीय स्थल ग्राम रामेश्वर है जो चंबल, सीप और बनास नदी के संगम पर स्थित है। इस क्षेत्र को बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है।

विजयपुर - विजयपुर शहर में तहसील मुख्यालय है। यह कुंवारी नदी पर स्थित है। इस कस्बे से विजयपुर टेंट्रा सड़क शुरू होती है। यह शहर राजस्थान के भरतपुर जिले में करौली राज्य के शासक विजय सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। पूर्व में विजयपुर एक परगना मुख्यालय था। इस स्थान पर एक स्कूल, डाकघर की एक शाखा, एक सयार चौकी और एक पुलिस स्टेशन था। शनिवार को यहां साप्ताहिक बाजार लगता है।

मानपुर का किला- श्योपुर से 45 किलोमीटर दूर राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया यह किला बाद में श्योपुर के गौड़ राजाओं के आधिपत्य में आ गया। सन् 1809 ई में दौलतराव सिंधिया ने इसे हासिल किया। किले में स्थित मानेश्वर महादेव मंदिर तथा राग-रागनियों के चित्र विशेष हैं।

बड़ोदा किला - खीची राजाओं द्वारा निर्मित, इस किले को राजा इंद्रासिंह गौड़ ने जीतकर श्योपुर रियासत का एक भाग बनाया था। किले में शीश महल, हवा महल, शंकर महल दर्शनीय हैं।

बंजारा डैम - मान्यता है कि सीप नदी पर स्थित बंजारा डैम लखखी बंजारे द्वारा बनाया गया था। इस डैम के निर्माण का प्रमाण सन् 1728ई. में राजा इन्द्रसिंह गौड़ द्वारा बनवाये जाने का मिलता है। बाद में जनकोजीराव सिंधिया द्वारा इस डैम की ऊंचाई बढ़ाई गयी थी, इस विवरण का शिलालेख बंजारा डैम की दीवार पर लगा हुआ है।

श्योपुर फोर्ट - सीप एवं कलवाल नदी के संगम पर बना यह किला प्रस्तर शिल्प का बेजोड़ नमूना है। पुरातत्व संग्रहालय में 425 मूर्तियों का भी संग्रह किया गया है। यहां स्थित गूजरी महल, नरसिंह महल, दरबार हॉल, राजा इन्द्र सिंह और राजा किशोरदास की छतरियां दर्शनीय हैं। किले के कुछ भवन संरक्षित घोषित हैं।

सहरिया संग्रहालय - श्योपुर किले में अत्यंत पिछड़ी सहरिया जनजाति की संस्कृति के संरक्षण के लिए सहरिया विकास प्राधिकरण, पुरातत्व तथा संस्कृति संरक्षण समिति के तत्वावधान में सहरिया संग्रहालय की स्थापना की गयी है। यह सहरिया संस्कृति का शोध केंद्र भी है।

गणगौर मेला - श्योपुर जिले में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। इसका नाम 'गण' और 'गौरी' शब्द से लिया गया है। यह महिलाओं का प्रमुख त्योहार है। इसमें विभिन्न रस्में शामिल होती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह चैत्र के महीने में आयोजित किया जाता है।

- देवेन्द्र गोरे

(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

खेल चर्चा

डब्ल्यूएफआई पर लगा निलंबन हटाया गया

नई दिल्ली, खेल मंत्रालय ने लगभग 15 महीने बाद भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) पर लगाया गया निलंबन हटा दिया है, जिससे खेल में बनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है और विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारतीय पहलवानों को आगामी प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए डब्ल्यूएफआई का निलंबन रद्द करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार डब्ल्यूएफआई को मान्यता देना आवश्यक था, ताकि हम अपने पहलवानों को एशियाई चैम्पियनशिप और विश्व चैम्पियनशिप जैसी प्रतियोगिताओं में भेज सकें। उल्लेखनीय है कि खेल मंत्रालय ने संचालन संबंधी गतिविधियों में खामियों के कारण 24 दिसंबर 2023 को डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया था।

आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी

तीसरी बार वन-डे विश्व चैम्पियन बना भारत

दुबई, भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर वन-डे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की विश्व चैम्पियन बन गई है। टीम इंडिया ने 12 वर्ष बाद आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। भारत ने तीसरी बार यह खिताब जीता है। टीम इंडिया तीन बार यह खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है।

मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड की शुरुआत शानदार रही। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरते हुए 7 ओवरों में ही स्कोर 50 रन के पार कर दिया। इसके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी आक्रमण पर स्पिनरों को लगाया। स्पिनरों के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। आठवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने विल यंग को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद कुलदीप यादव ने रचिन रवींद्र और केन विलियमसन को आउट कर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाला। डेरिल मिशेल ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए, वहीं फिलिप्स ने 34 रन बनाए। पारी के अंतिम ओवरों में माइकल ब्रेसवेल (53) ने तेजी से रन बनाए, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवरों में 251 रन बनाने में सफल रही।

- भारत ने तीसरी बार जीती है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी।
- इससे पहले भारत वर्ष 2002 (संयुक्त विजेता) और वर्ष 2013 में भी बना है चैम्पियन।
- भारतीय क्रिकेट टीम अब तक सात बार आईसीसी खिताब जीत चुकी है।
- यह भारत का लगातार दूसरा आईसीसी खिताब है।
- इससे पहले टीम इंडिया ने वर्ष 2024 में आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप जीता था।
- दो आईसीसी खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान है रोहित शर्मा।
- इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने जीते है तीन आईसीसी टूर्नामेंट।

पहले विकेट के लिए रोहित और शुभमन की शतकीय साझेदारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा ने तूफानी शुरुआत दिलाई। रोहित और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की शतकीय साझेदारी कर भारत को मजबूत शुरुआत दी। रोहित ने 76 रन तथा शुभमन ने 31 रन बनाए। विराट महज 1 रन ही बना सके। लगातार तीन विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर (48) और अक्षर पटेल (29) ने पारी को आगे बढ़ाया वहीं के.एल. राहुल ने एक बार फिर फिनिशर की भूमिका निभाई और नाबाद 34 रन बनाते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई। भारतीय टीम ने 49 ओवरों में 4 विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत के आईसीसी खिताब

वर्ष 1983	वन-डे विश्वकप
वर्ष 2002	चैम्पियंस ट्रॉफी
वर्ष 2007	ट्वेंटी-20 विश्वकप
वर्ष 2011	वन-डे विश्वकप
वर्ष 2013	चैम्पियंस ट्रॉफी
वर्ष 2024	ट्वेंटी-20 विश्वकप
वर्ष 2025	चैम्पियंस ट्रॉफी

टूर्नामेंट में अजेय रही टीम इंडिया

आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में नजर आई। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट के दौरान अजेय रही। टूर्नामेंट में भारत के कप्तान रोहित शर्मा भले ही एक बार भी टॉस नहीं जीत सके हो, लेकिन टीम इंडिया ने हर मैच में अपनी विरोधी टीम को पटखनी दी है। भारत ने चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया, वहीं दूसरे मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से हराने के बाद टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया तथा फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया।

भारत के प्रणव वेंकटेश बने विश्व जूनियर शतरंज चैम्पियन

मोंटेनेग्रो, डी. गुकेश के बाद भारत के एक और उभरते शतरंज खिलाड़ी प्रणव वेंकटेश ने विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। 17 वर्षीय प्रणव वेंकटेश ने मोंटेनेग्रो के पेट्रोवाक में आयोजित प्रतियोगिता के 11वें और अंतिम दौर में स्लोवेनिया के मैटिक लेवरेंसिक के खिलाफ ड्रॉ खेलकर विश्व जूनियर (अंडर-20) शतरंज चैंपियनशिप जीत ली।

वर्ष 2024 में चेन्नई इंटरनेशनल में चैलेंजर्स वर्ग का खिताब जीतने वाले प्रणव वेंकटेश ने दुनिया के जूनियर खिलाड़ियों के बीच अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपराजित रहे। भारतीय खिलाड़ी ने कुल सात जीत और चार ड्रॉ के साथ नौ अंक हासिल किए।

भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने प्रणव वेंकटेश की इस उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश को बधाई। वह शानदार फॉर्म में हैं। वह लगातार अपने खेल का विश्लेषण करते हैं, सुझाव देते हैं और फीडबैक लेते हैं। आप विश्व जूनियर चैंपियंस की एक बहुत ही प्रतिष्ठित पंक्ति में शामिल हो गए हैं।

- प्रणव ने छह वर्ष की आयु से ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था।
- वर्ष 2022 में रोमानिया के बाया मारे में लिम्पेडिया ओपन जीतकर प्रणव ने ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किया था।

टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल ने लिया संन्यास

नई दिल्ली, भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। कमल ने कहा कि इस महीने चेन्नई में आयोजित होने वाला डब्ल्यूटीटी कंटेंडर टूर्नामेंट पेशेवर खिलाड़ी के रूप में मेरा आखिरी टूर्नामेंट होगा। यह टूर्नामेंट 25 से 30 मार्च तक खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चेन्नई में खेला था और आखिरी टूर्नामेंट भी यहीं खेलूंगा।

लेब्रॉन 50 हजार अंक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने

लॉस एंजेलिस, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स ने बास्केटबॉल में नया इतिहास रच दिया है। लेब्रॉन अमेरिका की प्रमुख बास्केटबॉल प्रतियोगिता एनबीए लीग के इतिहास में 50 हजार अंक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। प्रतियोगिता में लॉस एंजेलिस लेकर्स के लिए खेलते हुए लेब्रॉन ने न्यू ऑरलियंस पेलिकंस के खिलाफ मैच में 17 अंक बनाने के साथ ही 50 हजार अंक का आंकड़ा छुआ।

भारत करेगा दूसरी एशियाई योगासन चैम्पियनशिप की मेजबानी

नई दिल्ली, भारत दूसरी एशियाई योगासन चैम्पियनशिप की मेजबानी करेगा। यह प्रतियोगिता 29 से 31 मार्च तक नई दिल्ली की इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता खेल मंत्रालय के भारतीय खेल प्राधिकरण और योगासन भारत के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

खेल मंत्रायल ने बताया कि इस चैम्पियनशिप में कम से कम 16 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, इसमें और भी कई देश शामिल हो सकते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य योगासन को एक खेल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देना है, साथ ही इसकी समृद्ध विरासत और गहरी सांस्कृतिक महत्ता का विश्व स्तर पर प्रसार करना है। योगासन को एक खेल के रूप में वैश्विक स्पर पर बढ़ावा देना और इसे एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में ओलंपिक में शामिल करने की दिशा में रोडमैप तैयार करना है। इस चैम्पियनशिप को एशियाई ओलंपिक परिषद, विश्व योगासन, एशियाई योगासन और योगासन इंद्रप्रस्थ सहित प्रमुख संगठनों का समर्थन प्राप्त है।

पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत ने जीते छह स्वर्ण पदक

विटोरिया, भारत के अनुभवी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने स्पेन के विटोरिया में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए छह स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में नितेश ने एसएल-3 वर्ग के फाइनल में जापान के डेसुके फुजिहारा को 21-19, 21-19 से हराया, वहीं सुकांत कदम ने एसएल-4 वर्ग के फाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी तरुण को 21-13, 21-10 से हराया। इसी तरह एसएच-6 वर्ग में नित्या श्रे ने पोलैंड के स्जमिगेल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता की पुरूष युगल वर्ग में नितेश और तरुण की जोड़ी ने खिताब जीता।

एशियन महिला कबड्डी चैम्पियनशिप

भारत पांचवीं बार बना विजेता

तेहरान, भारत ने एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप-2025 का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने मेजबान टीम ईरान को कड़े मुकाबले में 32-25 से हराया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने पांचवीं बार यह खिताब जीता है। आठ वर्ष के अंतराल के बाद इस टूर्नामेंट का छठा एडिशन ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित किया गया था। इससे पहले साल 2017 में इसे खेला गया था। तब भारत ने फाइनल में साउथ कोरिया को मात देकर इस टूर्नामेंट का चैंपियन बना था।

पूरे टूर्नामेंट में भारत का दबदबा

महिला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप-2025 में कुल सात टीमों ने हिस्सा लिया था। ग्रुप-ए में भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और मलेशिया की टीमें शामिल थीं। वहीं ग्रुप-बी में ईरान, ईराक और नेपाल की टीमें थीं। पूरे टूर्नामेंट में भारत का दबदबा देखने को मिला। भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज के दौरान अपने तीनों मुकाबलों में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इसके अलावा भारतीय टीम ने सभी टीमों से ज्यादा पॉइंट (213) स्कोर किए और सबसे कम पॉइंट (63) दिए थे। भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश को 64-23, थाईलैंड को 76-21 और मलेशिया को 73-19 के भारी अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

ग्रुप-ए से भारत के अलावा बांग्लादेश की टीम 3 में से 2 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। दूसरी ओर ग्रुप-बी में ईरान और नेपाल की टीमों ने सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी जगह बनाई। इसके बाद सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल की टीम से हुआ जिसमें भारतीय टीम ने 56-18 से एकतरफा जीत हासिल की।

- अब तक छह बार आयोजित की गई है एशियन महिला कबड्डी चैम्पियनशिप।
- भारतीय महिला टीम छह में से पांच बार बनी है चैम्पियन।
- भारत ने वर्ष 2005, 2007, 2008, 2017 और 2025 में जीते हैं खिताब।
- दक्षिण कोरिया एक बार वर्ष 2016 में बना है चैम्पियन।

फाइनल में रोमांचक मुकाबला

टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत और ईरान की भिड़ंत हुई। मैच में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। ईरान ने भारत को कांटे की टक्कर दी और मैच को रोमांचक बना दिया था, अंत में भारतीय टीम भारी रही और मुकाबले को 7 प्वॉइंट के नजदीकी अंतर से जीत लिया। ईरान को 32-25 से मात देकर भारत की महिला कबड्डी टीम एक बार फिर से एशिया की चैंपियन बन गई है।

फीफा ने पाकिस्तान, रूस और कांगो पर लगाया प्रतिबंध

डलास, फीफा ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा फुटबॉल विश्वकप से पाकिस्तान, रूस और कांगो को प्रतिबंधित कर दिया है। फीफा ने कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ ने निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देने वाला नया संविधान नहीं अपनाया है। वहीं यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस पर पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। फीफा ने कहा कि कांगो में लीग फुटबॉल फेडरेशन के प्रबंधन में अवैध तरीके से तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण कांगो पर प्रतिबंध लगाया गया है। फीफा ने कहा कि इस प्रतिबंध का मतलब है कि ये तीनों देश फीफा विश्वकप -2026 में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को मॉरीशस का सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्हें मॉरीशस के सर्वोच्च सम्मान 'द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन'' प्रदान किया गया। श्री मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। यह पुरस्कार भारत और मॉरीशस के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। यह किसी अन्य राष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी को प्रदान किया गया 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है।

दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास उत्तर कोरिया ने मिसाइलें दागीं

दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने ह्वांगहे प्रांत से कई बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में दागी हैं। यह घटना दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैन्य अभ्यास 'फ्रीडम शील्ड' के शुरू होने के कुछ घंटों बाद हुई। उत्तर कोरिया इसको अतिक्रमण का पूर्वाभ्यास मानता है।

अंग्रेजी अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अंग्रेजी देश में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा रही है, लेकिन यह कभी संघीय स्तर पर आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई थी। यूनेस्को के मुताबिक, दुनिया में अभी कुल 1.52 अरब लोग अंग्रेजी बोलते हैं और वह पहले स्थान पर काबिज है, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। दूसरे नंबर पर चीन और ताइवान में बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, जिसकी संख्या 1.14 करोड़ है।

कनाडा द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए रेजिडेंसी मार्ग की घोषणा

कनाडा सरकार ने निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए बड़े बदलावों की घोषणा की है। सीआईसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने 7 मार्च को निर्माण श्रमिकों के लिए स्थायी निवास के लिए एक नया मार्ग बनाने की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मॉरीशस की राजकीय यात्रा

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ बेहतर रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत-मॉरीशस संयुक्त रूप से प्रतिबद्ध

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मॉरीशस की राजकीय यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम, जीसीएसके, एफआरसीपी के साथ मॉरीशस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से व्यापक और उपयोगी चर्चा हुई। द्विपक्षीय बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने मॉरीशस और भारत के बीच उस विशेष और अद्वितीय संबंध की पुष्टि की जो इतिहास, भाषा, संस्कृति, विरासत, पारस्परिक संबंधों और मूल्यों के साझा बंधनों को देखते हुए अनुपम है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच आपसी सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर आधारित मॉरीशस-भारत संबंध पिछले कई दशकों में मजबूती से बढ़कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि स्वतंत्रता के समय से ही मॉरीशस के सामाजिक-आर्थिक विकास में विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका समय-समय पर सिद्ध होती रही है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मॉरीशस का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया है। उन्होंने भविष्य में विकास के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता प्रकट की।

सुरक्षा और विकास को उजागर किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मार्च 2015 में मॉरीशस की अपनी पिछली यात्रा को याद किया। उस दौरान भारत के 'सागर दृष्टिकोण', यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को उजागर किया गया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का राजकीय यात्रा के दौरान मॉरीशस में जोरदार स्वागत हुआ

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'सागर दृष्टिकोण' को साकार करने के लिए मॉरीशस एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में मॉरीशस सरकार के व्यापक समर्थन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मॉरीशस भारत के 'सागर दृष्टिकोण', 'पड़ोसी प्रथम दृष्टिकोण' और पिछड़े तथा विकासशील देशों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता के संपर्क बिन्दु पर खड़ा है। उन्होंने दोनों देशों के साझा लाभ के लिए इन नीतियों को आगे बढ़ाने में मॉरीशस की ओर से निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और विशिष्टता पर बल देते हुए, दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि इस रिश्ते को और अधिक दिशा प्रदान की जाए तथा इसे एक बेहतर रणनीतिक साझेदारी में बदला जाए।

राजनीतिक आदान-प्रदान

दोनों नेताओं ने माना कि उनके द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न स्तरों पर उच्च स्तर का विश्वास और आपसी समझ है, जिसे जारी रखने में दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और यात्राओं की अहम भूमिका है। यह भी उल्लेख किया गया कि भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत अतिथि देश के रूप में मॉरीशस की भागीदारी ने सभी क्षेत्रों में मेल-जोल और गहरी चर्चा को बढ़ावा दिया। दोनों नेताओं ने इन चर्चाओं को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

विकास साझेदारी

भारत, स्वतंत्रता के बाद से मॉरीशस के विकास के लिए अग्रणी भागीदार रहा है और इसके बुनियादी ढांचे और विकास से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने भारत-मॉरीशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, सर्वोच्च न्यायालय के नये भवन, नया ईएनटी अस्पताल, 956 सामाजिक आवास इकाइयां और शैक्षणिक टैबलेट जैसी कई उच्च प्रोफाइल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में भारत के सहयोग पर प्रकाश डालते हुए भारत से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही अगलेगा में भारतीय सहायता से विकसित नयी हवाई पट्टी और जेटी के लाभों और चक्रवात चिडो के बाद मॉरीशस के लोगों के लिए आपातकालीन मानवीय सहायता के प्रबंध में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप से बाहर निकला अमेरिका

गुजरी डेढ़ सदियों में बड़ी मात्रा में धरती को गर्म करने वाली गैसें छोड़ने वाले अमेरिका ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टनरशिप विकासशील देशों की मदद के लिए हुई थी। एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संधियों और वचनबद्धताओं से पल्ला झाड़ रहा अमेरिका अब जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (जेईटीपी) से अलग हो गया है। अमेरिका ने इस मुहिम में 9.3 अरब यूरो देने का वादा किया था। 2021 में शुरू की गई इस पहल की मदद से विकास कर रहे देशों को जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ले जाने के लिए अरबों डॉलर का फंड बनाया गया था। पार्टनरशिप में शामिल फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और डेनमार्क ने अब भी इसे जारी रखने का ऐलान किया है। ज्ञात रहे कि अमेरिका के जेईटीपी से बाहर होने का असर दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया समेत कई देशों पर पड़ेगा।

बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल का सफल परीक्षण

एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) ने एलसीए एएफ एमके1 प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान से देश में ही विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (बीवीआरएएएम) का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण के तहत उड़ते हुए लक्ष्य पर मिसाइल के सीधे प्रहार को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया। सभी उप-प्रणालियों ने सभी मिशन मापदंडों और उद्देश्यों को पूरा करते हुए सटीक प्रदर्शन किया। अस्त्र मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह 100 किमी से अधिक दूरी तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। यह उन्नत निर्देश और नेविगेशन क्षमताओं से लैस है जो मिसाइल को अधिक सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाते हैं। यह सफल परीक्षण एलसीए एएफ एमके1ए संस्करण को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सफलता एडीए, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की एकीकृत टीम की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इसमें सीईएमआईएलएसी, डीजी-एक्यूए, आईएएफ और टेस्ट रेंज टीम से भी सहयोग मिला है।

135वां स्थापना दिवस - 'ज्ञान भारतम् मिशन' भारतीय ज्ञान के भण्डार तक पहुंचने की दूरदर्शी पहल

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) नई दिल्ली में 135वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वास्तुकला पर केन्द्रित भारतीय विरासत की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया, जो हजारों वर्षों से चली आ रही विविध वास्तुकला के चमत्कारों में परिलक्षित होती है और उसमें विभिन्न शैलियां, प्रभाव और ऐतिहासिक काल शामिल हैं। श्री शेखावत ने कहा कि प्राचीन सिंधुघाटी सभ्यता से लेकर

मध्ययुगीन मंदिरों, मुगल स्मारकों और औपनिवेशिक युग की संरचनाओं तक, भारतीय वास्तुकला देश के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का वर्णन करती है।

विषयगत समूहों में वर्गीकृत किया

भारतीय विरासत की वास्तुकला संबंधी ऐतिहासिक धरोहरों के माध्यम से व्यापक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए, प्रदर्शनी ने इन स्थलों को विषयगत समूहों में वर्गीकृत किया, जिससे उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को गहराई के साथ समझा जा सके। अभिलेखीय भंडार से जुड़े कुछ मूल दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें आधिकारिक सरकारी फाइलें, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निजी कागजात, पुरातात्विक उत्खनन रिकॉर्ड, यूनेस्को के दस्तावेज और एनएआई लाइब्रेरी की दुर्लभ पुस्तकें शामिल थीं।

विरासत के संरक्षण पर प्रकाश डाला

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की सराहना की और भारत की समृद्ध दस्तावेजी विरासत के संरक्षण में इसके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटलीकरण कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसमें एक महीने में छह लाख से अधिक पृष्ठों का संरक्षण किया जा रहा है और प्रतिदिन उनमें से लाखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटलीकरण कार्यक्रम की सफलता ने 'ज्ञान भारतम् मिशन' के शुभारंभ को प्रेरित किया है, जो भारत के ज्ञान के विशाल भंडार तक पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से जुड़ी एक दूरदर्शी पहल है।

एक आधार पर जारी होगा एक यूएएन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों के लिए एक आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) जारी करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। इससे किसी कर्मचारी के नौकरी छोड़ने या दूसरी नौकरी पाने पर दो यूएएन नंबर नहीं होंगे। ईपीएफओ 3.0 के लागू होने के बाद यह नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। एक आधार पर एक ही यूएएन नंबर जारी होने के बाद सदस्यों को निकासी में दिक्कत नहीं आयेगी।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक- डॉ. सुदाम खाड़े, मुद्रक- डॉ. सुदाम खाड़े द्वारा मेसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक- रंजना चितले।